अप्रैल-2025 वर्ष-10 अंक-5

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

पहलगाम आतंकवादी हमला

द्वितीय
राम साहारिया मेमोरियल
पुरस्कार 2025

MBKM Foundation

मूल्य- ₹50/-

हम क्यों...

मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका है। हमारे समाज के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ बिन्दु तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे इसकी विषयवस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्व धर्म समभाव की भावना पर आधारित है। मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का एक प्रयास है । हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक सोच द्वारा समाज से जुड़े मूल मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है, जिससे देश में संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से ऊपर उठकर एक उच्चस्तरीय विचार-विमर्श का वातावरण तैयार हो सके।

MEDIA MAP
A Watchdog Of Liberal Democracy

सलाहकार मंडल
डॉ. रामजीलाल जांगिड
डॉ बलदेवराज गुप्त
डॉ जॉन दयाल
डॉ गौहर रजा
मंगल सिंह आजाद

संपादक :**प्रो प्रदीप माथुर**
संयुक्त संपादक : **डॉ सतीश मिश्रा**
सहयोगी संपादक : **प्रो शिवाजी सरकार**
विशेष प्रतिनिधि : **राजीव माथुर**
मुख्य सह-संपादक : **प्रशांत गौतम**
सह-संपादक : **अंकुर कुमार**
लखनऊ संवादाता : **ज़ेबा हसन**
पटना संवादाता : **अजय यायावर**
रायपुर संवादाता : **संदीप कुमार सिंह**

मुख्य प्रबंधक :**जगदीश गौतम**
विधि परामर्शदाता :**संजय माथुर**

पंजीकृत कार्यलय
2325, सेक्टर - डी , पॉकेट - 2 , वसंतकुंज , नई दिल्ली

कार्यालय
69 ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम गाजियाबाद-201014

दूरभाष - **9810385757 / 9910069262**

एम बी के एम फाउंडेशन प्रकाशन

ईमेल-**editor@mediamap.co.in**

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक प्रदीप माथुर द्वारा लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली से मुद्रित एवं मकान नंबर 70, ज्ञानखंड 4, इंदिरापुरम, जनपद-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित. सभी विवादों का निस्तारण जिला न्यायालय गाजियाबाद होगा ।

लेखों में उल्लेखित विचार लेखक के अपने हैं। लेखों और विचारो को लेकर किसी तरह का विवाद होने पर पत्रिका के संपादक और प्रकाशक, मुद्रक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जिला मुख्यालय गाज़ियाबाद ही होगा। इस पत्रिका से जुड़े सभी पदाधिकारी, सहयोगी और लेखक अवैतनिक हैं। पीआरबी एक्ट के तहत अंतर्गत संपादक प्रो प्रदीप माथुर उत्तरदायी है।

संपादकीय
पिछले अंक की एक झलक
विचार प्रवाह
सम-सामयिक

कश्मीर में आतंकवादी हिंसा का जिम्मेदार कौन ?	प्रो शिवाजी सरकार	8

राज्यों से

तमिलनाडु में परिसीमन और ' हिंदी का विरोध क्यों '	एन. सत्यमूर्ति	10

नजरिया उस पार का

पाकिस्तान पर मंडरा रहे गृह युद्ध के बादल दक्षिण एशिया में शांति के लिए खतरा	गोपाल मिश्रा	13

आर्थिक जगत

पूंजीवादी व्यवस्था का संकट : क्या मार्क्स की भविष्यवाणी सच हो रही है ?	धर्मेन्द्र आज़ाद	15

समाज

भारत का इतिहास और हिंदुत्व की धारणा : एक विश्लेषण	सुरैना अय्यर	17

धर्म दर्शन

महाबोधि मंदिर प्रबंधन: बौद्धों के साथ ऐतिहासिक अन्याय !	प्रशांत गौतम	19

दृष्टिकोण

डॉ अंबेडकर की वैचारिक यात्रा	नरेंद्र कुमार	21

कथा साहित्य

अनोखा बोझ	दिनेश वर्मा	23

पुस्तक समीक्षा

पाकिस्तान की दिशाहीन राजनीति	जगदीश गौतम	25
समकाल: जन आक्रोश को दर्शाती कविताएं	अंकुर कुमार	28

सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक युवा महिलाओ का सम्मान समारोह

द्वितीय वार्षिक डॉ. रमा सहारिया मेमोरियल पुरस्कार समारोह		29

पिछले अंक की एक झलक

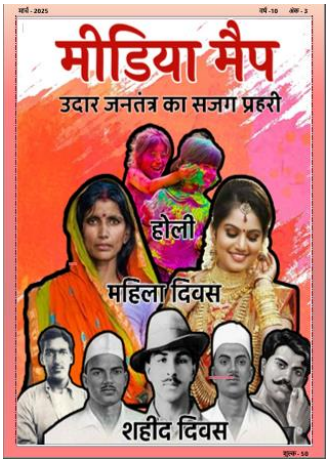

गिग इकॉनमी से श्रमिक अधिकारों का हनन

भारत की अर्थव्यवस्था, जो अपनी गति पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, एक नई चुनौती का सामना कर रही है। यह चुनौती है गिग वर्कर्स की बढ़ती संख्या, जिन्हें नीति आयोग जैसे संस्थान सम्मानित श्रमिकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये गिग वर्कर्स, जो भारत के सबसे तेजी से बढ़ते कार्यबल का हिस्सा हैं, अक्सर अनिश्चित परिस्थितियों में काम करते हैं। नौकरी खोने और भुखमरी के डर से कई श्रमिक अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में असमर्थ रहते हैं।

~ प्रो शिवाजी सरकार

****

महाकुंभ और भाजपा की चुनावी संभावनाएं

संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले या ऐसा करने की प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं को ही पता है कि महाकुंभ का उनके मोक्ष प्राप्ति की संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन देश के राजनीतिक परिदृश्य पर महाकुंभ का प्रभाव स्पष्ट है। महाकुंभ के बाद हमारे देश में राजनीति, खासकर सत्तारूढ़ भाजपा के बारे में, वैसी नहीं होगी जैसी पिछले महीने धूमधाम से शुरू हुए इस आयोजन से पहले थी।

~प्रो प्रदीप माथुर

****

अमेरिका के विरुद्ध एकजुट होते पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश

नेतन्याहू की मौजूदगी में ट्रंप की दुर्भावनापूर्ण योजना मूलतः गाजा में उनकी संयुक्त हार की स्वीकृति है। इस योजना ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि तमाम तबाही के बावजूद गाजा पर जबरन कब्जा या इसके बहादुर लोगों को भागने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।

डॉ. सलीम खान

****

केजरीवाल की राह पर चलते प्रशांत किशोर

अरविंद केजरीवाल की "वैकल्पिक राजनीति" का हश्र प्रशांत किशोर देख रहे होंगे जो आजकल बिहार में तंबू टांग कर नई पीढ़ी को सत्याग्रह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे हाल फिलहाल तक अपने "जन सुराज" और अनशन को लेकर मीडिया में बहुत चर्चा पाते रहे थे। फिर, नित नई खबरों के रेले में कहीं गुम से हो गए हैं।

~ प्रो. हेमंत कुमार सिंह

संपादकीय

भारत-अमेरिका संबंधों पर ट्रंप की उपेक्षा: क्या हमें चिंतित होना चाहिए?

प्रो प्रदीप माथुर

नई दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक में स्थित हमारा विदेश मंत्रालय, जो भी कहें, सच्चाई यह है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत के प्रति रुख पहले दिन से ही उपेक्षापूर्ण और अवमाननापूर्ण रहा है। कैसे? जरा इसे देखें:

* चीनी राष्ट्रपति और कई छोटे देशों के नेता राष्ट्रपति उद्घाटन में आमंत्रित होते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया जाता।

* कहा जाता है कि हमारे विदेश मंत्री नौ दिन तक आमंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते।

* जैसे भारतीय सरकार को चिढ़ाने के लिए, उद्योगपति मुकेश अंबानी को एक कॉर्पोरेट प्रमुख के सुझाव पर उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया जाता है।

* जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें एक जूनियर अधिकारी द्वारा स्वागत किया जाता है, जबकि ट्रंप खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति को स्वागत करने के लिए बाहर आए थे।

* प्रधानमंत्री मोदी से अपनी बातचीत के दौरान, ट्रंप अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में बंद कर निष्कासित करते हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि इसे कुछ दिन के लिए टाला क्यों नहीं जा सकता था और हमारे प्रधानमंत्री को लौटते वक्त शर्मिंदगी का सामना क्यों किया गया।

* मोदी की उपस्थिति में, ट्रंप बीआरआईसीएस पर तीखा हमला करते हैं और धमकी देते हैं। भारत बीआरआईसीएस का एक प्रोत्साहक और एक महत्वपूर्ण सदस्य है।

* एलोन मस्क हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय अधिकारियों के साथ अपनी संतान और नानी के साथ मुलाकात करने आते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री की गरिमा को घटित करता है।

* जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा से लौटते हैं, ट्रंप यह घोषणा करते हैं कि यूएसएआईडी ने उनके दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट के लिए एक बड़ी राशि दी।

* वह फिर भारत को आयात शुल्क से धमकी देते हैं, जो वह कहते हैं कि अगले अप्रैल 2 से लागू होगा।

* हम यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही ट्रंप हैं जिन्होंने अपनी पिछली अवधि में भारत को धमकी दी थी और मजबूर किया था कि वह कोविड के दौरान कम उत्पादन वाली एक आवश्यक दवा अमेरिका को आयात करे।

सच यह है कि ट्रंप एक उत्पीड़क हैं, जो शक्ति की भाषा को समझते हैं, न कि शराफत की। चीन के खिलाफ बोलने के बाद, अब वह उसके साथ सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा और यूरोप और पश्चिम एशिया के कई देशों ने उनकी नीतियों का खुला विरोध शुरू कर दिया है और अब वह दबाव में झुकते हुए दिख रहे हैं। और तो और, चुनाव के 100 दिनों के भीतर ट्रंप की आर्थिक नीतियों और राजनीतिक दृष्टिकोण का विरोध उनकी अपनी धरती पर शुरू हो गया था।

वास्तव में ट्रंप अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक अजूबा हैं। उन्हें न वह इतिहास पता है, जिसने अमेरिका को आधुनिक युग का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाया है, और न ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतिक संवादों के शिष्टाचार का ज्ञान है। रियल एस्टेट व्यापार से राजनीति में आए ट्रंप समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, और अगर आपके पास पैसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि अमेरिका के पास पैसा है, ट्रंप मानते हैं कि उनका हर सही या गलत रुख दुनिया को स्वीकार करना चाहिए।

भारत ने लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के खिलाफ एक स्वतंत्र कदम उठाते हुए देखा, जबकि शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और रिचर्ड निक्सन ने वर्ष 1965 और 1971 में उन्हें दबाने की कोशिश की थी। और यह उस समय हुआ था जब भारत बहुत कम विकसित था और आज की तरह सैन्य और वित्तीय दृष्टि से इतना मजबूत नहीं था। ये भारतीय नेता जानते थे जैसे दुनिया के तमाम अन्य लोग जानते हैं कि पैसा, सैन्य शक्ति और उद्यत वाक्यांशों के अलावा, अमेरिकी नेता कागज के शेर होते हैं। कम्युनिस्ट चीन, उत्तर वियतनाम, उत्तर कोरिया और ईरान ने हमेशा अमेरिका का विरोध किया और अमेरिका उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। अफगानिस्तान जैसे छोटे और गरीब देश ने उनको खदेड़कर बाहर कर दिया। इसलिए हमें ट्रंप से डुबने का कोई कारण नहीं है।

हमें ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी आर्थिक लाभ को नजरअंदाज करना चाहिए, जैसे कि अमेरिका से हम क्रूड ऑयल और मावे जैसी कई चीजें आयात कर रहे हैं, जो हम अपने पड़ोसी देशों से सस्ते में मंगवा सकते हैं। व्यापार में जो भी नफा-नुकसान हो, जरूरी यह है कि हमें अपने आत्म-सम्मान पर खड़ा होना चाहिए, जैसा कि एक बड़े और महान देश के रूप में भारत के लिए उपयुक्त है।

हमारा महान देश और उसकी संस्कृति सदियों से जीवित रही है और पली-बढ़ी है, और तब जब आज का अमेरिका नहीं था, और अब कोई कारण नहीं है कि हम ट्रंप के अमेरिका की दयालुता के बिना नहीं रह सकते।

****

भारत में एलन मस्क के स्टारलिंक की एंट्री

एलन मस्क के भारत आगमन और उनकी कंपनी स्टारलिंक की टेलीकॉम सेवाओं को लेकर कई चर्चाएँ हो रही हैं। पहले टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जियो-एयरटेल जैसे भारतीय टेलीकॉम दिग्गजों के विरोध के कारण स्टारलिंक को अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा और मस्क से मुलाकात के बाद परिस्थितियाँ बदली हैं।

स्टारलिंक के आने से टेलीकॉम सेवाएँ सस्ती होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसकी सेवाएँ जियो और एयरटेल से 14 गुना महंगी हैं। तकनीकी रूप से भी यह भारत में पहले से उपलब्ध 5G से बेहतर नहीं है। स्टारलिंक दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा ला सकता है, लेकिन इसकी ऊँची लागत इसे आम जनता की पहुँच से बाहर कर सकती है। इसलिए, यह शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे बड़े बाजार में उसकी कंपनियाँ आगे बढ़ें। भारतीय टेलीकॉम कंपनियाँ पहले इसका विरोध कर रही थीं, लेकिन अब उन्होंने अपना रुख बदल लिया है, जिससे बाहरी दबाव का संकेत मिलता है। साथ ही, विदेशी कंपनियों की उपस्थिति डेटा प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

भारत को अमेरिकी दबाव से बचकर अपनी नीतियाँ स्वतंत्र रूप से तय करनी चाहिए। सरकार को इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस कराकर दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

अन्याय के ख़िलाफ़ खड़ी होने वाली रंजनी श्रीनिवासन

समाज में जब भी शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठती है, सत्ता उसे कुचलने की हरसंभव कोशिश करती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सच्चाई के साथ खड़े होने वालों को तरह-तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी हैं—कभी निर्वासन, कभी रोज़गार छिन जाना, तो कभी ज़िंदगी तक दांव पर लगानी पड़ी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यक्तिगत नुकसान की परवाह किए बिना अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं। रंजनी श्रीनिवासन उन्हीं बहादुर लोगों में से एक हैं।

रंजनी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थीं। लेकिन जब इजरायल की बर्बरता के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, तो उन्होंने चुपचाप देखने की बजाय खुलकर उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अन्याय के विरोध में खड़े होने का

निर्णय लिया। लेकिन पूंजीवादी-साम्राज्यवादी सत्ता को यह सहन नहीं हुआ—ट्रंप सरकार ने उनका वीज़ा रद्द कर दिया। यह सज़ा थी उनके सच्चाई के साथ खड़े होने की। लेकिन सच्चे क्रांतिकारी डरते नहीं—वे लड़ते हैं।

रंजनी ने भी झुकने की बजाय कनाडा का रुख किया और साफ शब्दों में कहा कि उनका इजरायली बर्बरता के ख़िलाफ़ खड़ा होना सही था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस वजह से उनका करियर समाप्त होता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने इंसानियत का साथ दिया।

यह घटना कोई व्यक्तिगत कहानी भर नहीं है, बल्कि एक बड़े संघर्ष का हिस्सा है। यह सत्ता के उस चेहरे को उजागर भी करती है जो केवल अपने फायदे के लिए नैतिकता और न्याय को कुचलने से पीछे नहीं हटती। यह दिखाती है कि किस तरह शोषक ताकतें हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करती हैं, जो उनके अत्याचार के खिलाफ उठती है।

रंजनी श्रीनिवासन का यह साहस हमें याद दिलाता है कि इतिहास बनाने वाले साहसिक छात्रों का जीवन केवल किताबों या करियर तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वे अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जब तक दुनिया में शोषण, उत्पीड़न, दमन, अन्याय, ग़ैर बराबरी मौजूद है, तब तक ऐसे ही लोगों की ज़रूरत रहेगी, जो अपने हितों से ऊपर उठकर समाज के हक़ में लड़ने का माद्दा रखते हैं। रंजनी की यह लड़ाई जारी रहेगी—हमेशा, हर जगह, हर रूप में। भारत की इस बहादुर बेटी को सलाम!

—धर्मेन्द्र आज़ाद

कश्मीर में आतंकवादी हिंसा का जिम्मेदार कौन ?

प्रो शिवाजी सरकार

जम्मू और कश्मीर आज़ादी से आज तक ख़बरों की सुर्खियों में है. अप्रैल २२ को हुए आतंकी हमले में २९ लोगों की मौत हुई. सन १९४८ से मौत, कबाइली घुसपैठ, पाक फौजियों छद्मवेश में आक्रमण, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश और कभी मुस्लिमों को हिन्दुओं के खिलाफ भड़काकर हिन्दुओं को भगाना आम बात रहीं है. कश्मीर सुलझ नहीं रहा है.

हमारे तमाम आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद भी कश्मीर का निर्णय न जम्मू कश्मीर के लोग कर रहें है, न भारत सरकार. यह पाकिस्तान के चालों के जाल में फंसा हुआ है और हम अच्छी अच्छी बातें करते है, पर रियेक्ट सिर्फ पाकिस्तानी चालो पर करते हैं. अप्रैल २२, २०२५ की पहलगाम के बैसरन टूरिस्ट घाटी की घटना, पुलवामा के बाद से सबसे बड़ी घटना है. हमारे पास खबर, भुताना, लिखना और आतंकियों के धमकी के प्रसार के अलाव और कुछ करने को नहीं है. हाँ, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विपक्ष के तमाम नेतोओं के कड़ी आलोचना भी हमारी ताकत को बढ़ाते है.

क्या खुफिया तंत्र जैसे पुलवामा में नाकामयाब थी यहाँ भी है? दिखता तो ऐसा ही है. पुलवामा २०१९ के

चुनाव से चंद दिनों पहले हुआ, और बैसरन जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे तब हुआ. उन्हें दौरा जल्दबाजी में ख़त्म करना पड़ा. यह इत्तेफाक नहीं है कि अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जब वे भी भारत दौरे पर है. क्या यह लश्कर-ए-तैयबा का अमेरिका को चुनौती है? लश्कर-ए-तैयबा के The Resistance Front (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली. यानि लश्कर-ए-तैयबा का यह भारत और अमेरिका को खुली चुनौती है. अमित शाह श्रीनगर पहुँच गए.

यह साफ़ है कि इस बारे में न भारत को पता था न ही अमेरिका को. यानि दोनों देशों के खुफिया तंत्र को इसकी खबर नहीं थी. मिशन आसान था. कुल पांच लोग जंगल से निकले. सैलानियों के पास पहुंचे. उनके कपडे उतार कर उनकी धर्म की शिनाख्त की और आराम से गोली मरकर चले घूम घूम कर नाम व धर्म पुछा और करीब से गोली मारी. उन्हें इत्मिनान था कि फौज तो दूर कोई पुलिसवाला भी वहां उनको रोकने के लिए नहीं है. क्या

इसकी कुछ भनक थी इसीलिए प्रधानमत्री का अप्रैल 19 का कश्मीर दौरा जो रोका गया था. शायद नहीं. ज़ाहिर तौर पर यह रामबन और मौसम के मिजाज बिगड़ने से जुड़ा था. एक सवाल तो उठता ही है. जहाँ रोज इतने सैलानी जाते है, वहां कुछ सिपाही रखने के भी जरूरत किसी ने महसूस नहीं की? बेशक जन्नत में व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है. पर पहलगाम और बिसारना तो धरती के ऐसे हिस्से में है जहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है. पर इतनी चैन कहाँ से और कैसे जम्मू कश्मीर के सरकार के मुलाजिमों को आई? इस सवाल का जवाब शायद ही कभी मिले.

कहा जा रहा है की पाकिस्तान के फ़ौज जनरल असीम मुनीर ने अपने बलोचिस्तान को लेकर हालिया बयाँ में हिंदुस्तान को चेतावनी दी थी. जानकार मानते है कि पाकिस्तानी फ़ौज बलूचिस्तान में बगावत से परेशान है. एक ऐसे देश में जहाँ सेना का नेतृत्व अक्सर राजनीति से जुड़ा होता है, जनरल मुनीर की टिप्पणियाँ इस्लामाबाद के कई मुद्दों पर रुख को स्पष्ट करती हैं, खासकर भारत के साथ संबंधों को लेकर उनके दृष्टिकोण को। वे दोहरे राष्ट्रवाद सिद्धांत को दोहराते हैं, जिससे पाकिस्तानियों में एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है—जो देश के लिए इस चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक है। उनकी टिप्पणियाँ यह भी दर्शाती हैं कि सशस्त्र बल पाकिस्तान की इस्लामी पहचान और संप्रभुता के रक्षक हैं। कश्मीर को लेकर दिए गए बयान यह स्पष्ट करते हैं कि यह मुद्दा अभी भी भारत-पाक संघर्ष के

> 1948 से लेकर आज तक, कश्मीर सिर्फ ख़बरों में नहीं, ज़ख्मों में भी जिंदा है। आतंकी हमलों, घुसपैठ और धार्मिक उकसावे ने इस जन्नत को जलता नर्क बना दिया है। क्या हम सिर्फ प्रतिक्रियात्मक राष्ट्र रह गए हैं?

केंद्र में है और इस्लामाबाद की स्थिति में नरमी लाने की कोई योजना नहीं है।

पाकिस्तानी जनरल की टिप्पणियों में दिखा भारत-विरोधी रुख दोनों देशों के बीच दुश्मनी को और गहरा कर सकता है। मुनीर के इस बयां को अगर TRF के कार्रवाई से जोड़े तो साफ़ नज़र आता है की पाकिस्तान इस वाकये से जुडा है.

पर फिर भी सवाल रहते है की हिंदुस्तान के तंत्र को इन बातों की खबर क्यों नहीं थी. हमारा मुल्क बेखबर कैसे रह सकता है.

प्रश्न है कि क्या हिंदुस्तान कोई कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है. करना तो चाहिए पर करना आसान नहीं होगा. कार्रवाई पाकिस्तानी फ़ौज पर करना है. पाकिस्तानी जनरल का हालिया बयां सियासी ज्यादा लगता है. हिंदुस्तान को कुछ करना तो होगा पर सोच समझ कर. लड़ाई छेड़ना देश के माली हालात को दखते हुए आसान नहीं है. जंग अगर कामयाबी लाती है तो फ़ायदा है. हम कैसे करें और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या मिलेगा इसके अंदाज़ करने के बाद ही हो सकेगा. तब तक उम्मीद है कि और आतंकी घटना के लिए भारत का तंत्र तैयार रहेगा।

लेखक
वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया शिक्षक है।

****

तमिलनाडु में परिसीमन और 'हिंदी का विरोध क्यों'

- **एन. सत्यमूर्ति**

एन. सत्य मूर्ति

विंध्याचल के पार से आने वाले अनजान लोग यह सोच रहे होंगे कि अचानक तमिलनाडु में जो विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं, क्या यह एक बार फिर से उत्तर भारत के खिलाफ और कभी-कभी 'देशद्रोही' 'द्रविड़ राजनीतिक विरोध' हैं, जिनका 21वीं सदी के 'भारत' या 'भारत जो इंडिया है' से कोई लेना-देना नहीं है।

जैसे वे यह शिकायत करते हैं कि आज की तमिल पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के समय से जुड़ी पुरानी बोझिल यादों से जूझना पड़ता है, वैसे ही उनका भी अतीत अधिक गहरे घावों से भरा हुआ है, जिसे वे न तब समझ पाए थे और न अब समझ पा रहे हैं।

शुरुआत करते हुए, हाल के तमिल विरोध प्रदर्शन, जो 'परिसीमन' और 'हिंदी-परिवर्तन' पर केंद्रित हैं, का एक लंबा इतिहास है। दोनों विषय एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन मिलकर यह 'तमिल पहचान'

> तमिलनाडु में उठते विरोध प्रदर्शन क्या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हैं या इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ छिपा है? परिसीमन और हिंदी-प्रवर्तन पर बढ़ती बहस दरअसल तमिल पहचान की पुनर्स्थापना का संकेत है।

राजनीति के पुनर्जीवन को उत्तेजित करते हैं, जिसे नया सदी/हजाराब्दी के मोड़ पर लंबे समय तक भुला दिया गया था। उस अंतराल में, द्रविड़ राजनीतिक पहचान, विभिन्न चुनावी पहचान से परे, दशकों पुरानी सैद्धांतिक से हटकर एक अधिक पहचानने योग्य और प्रतिस्पर्धी विकासात्मक कार्यक्रमों की ओर बढ़ गई थी, जब वे निर्वाचित सत्ता में थे।

मुख्यधारा में शामिल होने वाले द्रविड़ मुनेत्र कश्मगम (DMK), जिसने एक अलग 'द्रविड़ नाडु' का प्रचार किया था, 'पेरियार' ई वी रामास्वामी (ईवीआर) द्वारा संस्थापित डॉ. कांची (DK) से विरासत में मिला था, और 1967 में पार्टी का चुनावी सत्ता में उत्थान, यह दिखाता है कि भारतीय संविधान योजना उन्हें सहजता से आत्मसात कर सकती है और उनके विविध और विभाजित सामाजिक-राजनीतिक विचारधारा को समाहित करने के लिए अंतर्निहित प्रावधान भी हैं।

ऐसा याद रखें कि जो कुछ भी द्रविड़ समाज-राजनीतिक

विचारधारा के रूप में मनाया जाता है, वह स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और बाद में एक चौथाई सदी से अधिक समय तक अस्तित्व में था, इससे पहले कि देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की, और फिर गणराज्य का निर्माण किया और 'भाषाई राज्यों' का गठन किया, जो स्वतंत्रता के पहले दशक के भीतर हुआ।

ऐतिहासिक रूप से, तमिलनाडु ब्रिटिश उपनिवेशी शासकों के नियंत्रण से पहले सदियों तक विकसित हो चुका था। यह सच है कि राज्य और/या क्षेत्र खैबर दर्रे के पार से होने वाली आक्रमणों के प्रकोप का शिकार नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी, राज्य का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, चेरस, चोलस, पाण्ड्यस और पलवास के तहत बाबर के आगमन से पहले का था, लेकिन निश्चित रूप से 'गुलाम वंश' और दिल्ली सल्तनत के युग को शामिल करता था।

यह भी सच है कि तटीय देश/राज्य अक्सर फलते-फूलते हैं, जबकि उनका आंतरिक इलाका गरीब रहता है। हालांकि, 'प्राचीन भारत' और आज के विकसित पूरब और पश्चिम, जैसे ओडिशा और गुजरात के बीच कोई तुलना नहीं है। जैसे वर्तमान तमिलनाडु ने समुद्री व्यापार में लंबा और सफल करियर बिताया और उसके परिणामस्वरूप समृद्धि आई, वैसे ही गुजरात ने तमिलनाडु के साथ पहले कदम मिलाया और पिछले

> क्या द्रविड़ राजनीति को भारत की मुख्यधारा से अलग समझना सही है? स्वतंत्रता संग्राम से पहले की सामाजिक न्याय की यह लड़ाई आज भी कई स्तरों पर कायम है।

कुछ दशकों में उसे पीछे छोड़ दिया। दुर्भाग्यवश, ओडिशा कई पीढ़ियों और सदियों पहले कठिन समय में गिर गया था, और अब तक वह खोई हुई ज़मीन और महिमा को वापस नहीं पा सका।

इसका मतलब यह था कि अन्य स्थानों पर युद्धों और हिंसा से कम प्रभावित होते हुए, तमिल समाज उन सामाजिक संकेतकों में आगे बढ़ रहा था जो उस समय उपलब्ध थे। यह ब्रिटिश राज के तहत और अधिक प्रगति की, जब चेन्नई, तब मद्रास, पहले राजधानी था, फिर कोलकाता (अब कोलकाता) और बाद में दिल्ली को स्थानांतरित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, यह एक नया सामाजिक-राजनीतिक जागरण था, जो 20वीं सदी के मोड़ पर 'सामाजिक न्याय' आंदोलन की शुरुआत की ओर ले गया।

राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करना

इस संपूर्ण पृष्ठभूमि और संदर्भ में, वर्तमान 'संकट के मुद्दों' का अध्ययन और समझना आवश्यक है। चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, 'द्रविड़ राजनीतिक पहचान' राष्ट्रीय पहचान से पुरानी है। शिकायत, चाहे सही हो या गलत, यह है कि इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से समाहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। जब भी इस विषय पर कोई विमर्श, बहस या मतभेद होते हैं, तो आरोप-प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो जाता है, जिसमें 'राष्ट्रवादियों' द्वारा द्रविड़ नेताओं और विचारकों को दोषी

ठहराया जाता है, और बाद में ये आरोप केंद्र सरकार के पक्ष में वापस जाते हैं।

यह वही हुआ है इस बार भी। उदाहरण के तौर पर, परिसीमन विवाद इस बड़ी तमिल नाराजगी के आसपास घूमता है कि राज्य को पहले और फिर तेजी से विकसित होने के लिए लगातार दंडित किया जा रहा है, और इस तरह के विकास और वृद्धि सामाजिक संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आलोचक, जो लोकसभा के राष्ट्रीय चुनावों के लिए वर्तमान सीट-साझाकरण योजना पर सवाल उठा रहे हैं, बताते हैं कि

जनसंख्या नीति और संसदीय सीटों के पुनर्समायोजन को लेकर तमिलनाडु में बढ़ता असंतोष क्या केंद्र-राज्य संबंधों में नई दरार डाल रहा है? जानिए इसकी गहरी पड़ताल।

राज्य का राष्ट्रीय राजस्व में हिस्सा घट रहा है, क्योंकि अन्य राज्यों ने समय पर और प्रभावी रूप से राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता जताई है।

इस मुद्दे का अंत यहीं नहीं है। एक अन्य दस्तावेज है जिसे 'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति' कहा जाता है, जिसका अंतिम संस्करण 2000 में जारी किया गया था। यह दस्तावेज़ अधिकारियों को जनसंख्या प्रबंधन पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

अगर यह परिसीमन के साथ ऐसा है, तो 'हिंदी-प्रवर्तन' का मुद्दा कहाँ आता है? तात्कालिक उत्तेजना किसी द्रविड़ संस्था से नहीं आई, बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आई। तमिलनाडु के लगातार अनुरोधों के बावजूद ₹2000 करोड़ से अधिक की राशि जो राज्य को 'PM-SHREE' योजना के तहत मिलनी थी, प्रधान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये धनराशि केवल उन राज्यों को उपलब्ध होगी जिन्होंने केंद्र की 'नई शिक्षा नीति' (NEP) को लागू किया। NEP ने तमिलनाडु पर तीन-भाषा नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा था, जबकि तमिलनाडु ने हमेशा केवल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई हैं और हिंदी को वैकल्पिक रूप से रखा है।

नौकरी के अवसर

यहां पर तीन-भाषा फार्मूला को लागू करने वाले लोग, विशेष रूप से बीजेपी-आरएसएस के लोग, अपने तर्कों में विफल हो जाते हैं। जैसा कि दूसरी ओर से बताया गया है, यह तर्क कि हिंदी को न सिखाने से तमिलनाडु के लोग उत्तर भारत में नौकरी के अवसरों से वंचित हो रहे हैं, व्यवहारिक रूप से गलत है।

हिंदी बनाम तमिल: शिक्षा नीति की उलझन

तीन-भाषा नीति और नई शिक्षा नीति (NEP) को लेकर तमिलनाडु में क्यों बढ़ रहा है विरोध? क्या यह भाषाई अस्मिता की लड़ाई है या रोजगार के अवसरों की नई चुनौती?

व्यवहारिक दृष्टिकोण

इस प्रकार, चाहे वह परिसीमन हो, हिंदी का प्रवर्तन हो या व्यापक NEP/NEET कार्यान्वयन, केवल तमिल गौरव ही आहत नहीं हुआ है। इनमें से सभी में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो लंबे समय से मौजूद है।

****

पाकिस्तान पर मंडरा रहे गृह युद्ध के बादल दक्षिण एशिया में शांति के लिए खतरा

-गोपाल मिश्रा

गोपाल मिश्रा

पहले रावलपिंडी में सेना के प्रवक्ता ने नई युद्ध रणनीति की घोषणा की, दो दिन बाद पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने नेशनल असेंबली को बताया कि आंतरिक खतरा गंभीर है और विदेशी ताकतों द्वारा समर्थित है।

इस बीच, पाकिस्तानी मीडिया ने बलूच विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू कर दिया है।

इस पृष्ठभूमि में, यह काफी आश्चर्यजनक है कि अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गब्बार्ड की 60 घंटे की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत ने क्षेत्र में शांति के लिए बढ़ते खतरे का मुद्दा क्यों नहीं उठाया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके बजाय भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका में अलगाववादी खालिस्तानियों की गतिविधियों का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रयाग में संपन्न कुंभ से तुलसी गबार्ड को पवित्र जल की एक बोतल भेंट की, जहां गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है।

उनकी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में 20 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सुरक्षा सम्मेलन भी हुआ। हालांकि, इसमें पाकिस्तान के दो सीमावर्ती प्रांतों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) के लोगों पर पाकिस्तानी सेना के दमन और शोषण के खिलाफ विद्रोह का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये लोग युद्ध के रास्ते पर हैं।

भारत के खिलाफ आरोपों के साथ, चल रहा विद्रोह भारत की सीमा से लगे सिंध और पंजाब तक फैल सकता है। 1970-71 की अवधि का सबसे खराब परिदृश्य,

> पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने नेशनल असेंबली में आंतरिक खतरे को गंभीर बताते हुए विदेशी ताकतों की साजिश का जिक्र किया। इसी बीच, पाक मीडिया ने भारत पर बलूच विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया।

जब पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से के बहुसंख्यक मुस्लिम बांग्लादेश बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, शायद हमारा इंतजार कर रहा है।

नई दिल्ली में विदेश और सामरिक मामलों के विद्वानों के बीच यह आशंका बढ़ती जा रही है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों और चीन का समर्थन पाने के लिए इस्लामाबाद भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। इसकी जमीनी तैयारी पूरी तरह से की जा रही है।

साउथ ब्लॉक में, जहां तीन प्रमुख मंत्रालय, रक्षा, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय स्थित हैं, ऐसी अफवाहें हैं कि शांति के लिए तात्कालिक खतरों से संबंधित मुद्दों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, लेकिन कभी भी उन्हें स्पष्ट नहीं किया गया।

अवसर चूक गया

यह काफी दिलचस्प है कि भारतीय अधिकारी तुलसी को तथा रायसीना डायलॉग के बैनर तले आयोजित सम्मेलन में यह बता सकते थे कि दोनों प्रांतों में चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष का कारण वास्तव में पाकिस्तान में वर्दी के सख्त नियंत्रण के तहत सैन्य शासन की गैर-प्रतिनिधि प्रकृति है।

बलूचों का न केवल पाकिस्तान शोषण कर रहा है, बल्कि उसकी सेना उनके प्रांत में दुर्लभ खनिजों का अवैध खनन करने में लगी हुई है। यहां तक कि चीनी ट्रॉलरों द्वारा मछलियां पकड़ने के कारण गरीब बलूच मछुआरों को भी वंचित होना पड़ रहा है। दूसरी ओर, पीओके

लोग डुरंड रेखा को मानने से इनकार करते हैं, जो प्रांत के लोगों को विभाजित करती है।

यह काफी दिलचस्प है कि इस्लामाबाद की ओर से स्पष्ट धमकियों के बावजूद, इस मुद्दे को न तो तुलसी गबार्ड के समक्ष उठाया गया और न ही 17-18 मार्च को आयोजित दो दिवसीय सुरक्षा सम्मेलन के समक्ष उठाया गया।

क्या यह अंबानी फैक्टर हो सकता है?

हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल के वर्षों में मुकेश अंबानी फैक्टर देश की विदेश नीति के प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से महसूस किया जा रहा है। यहां तक कि रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भी पहले एक सम्मेलन में आयोजकों से कहा था कि उनसे पूछने से पहले "अपने सवालों को वाशिंगटन से सत्यापित करवा लें"।

हालांकि, तुलसी की भारतीय राजधानी में मौजूदगी का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। वह रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग के तहत सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की बैठक के दौरान भारत में थीं। रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग अंबानी के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) और भारत के विदेश मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है।

स्पिनऑफ्स सुरक्षा के लिए रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण के दो दिवसीय सत्र का प्रभाव अभी पता लगाया जाना बाकी है। सम्मेलन *कालचक्र* की थीम पर केंद्रित था, यानी लोगों, शांति और ग्रह पर ध्यान केंद्रित करना। भारत के पड़ोस से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर इस हाई-प्रोफाइल सम्मेलन में ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुलसी की संक्षिप्त उपस्थिति ने प्रतिभागियों का आत्मविश्वास बढ़ाया होगा, खासकर इस क्षेत्र में भारत की भूमिका के संदर्भ में। यह उम्मीद की जा रही थी कि उनकी उपस्थिति से क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता में भारत के अधिक महत्वपूर्ण योगदान की पुनः शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐसा वर्तमान खतरों की अनदेखी करके नहीं किया जा सकता।

इस क्षेत्र में चीन की आर्थिक स्थिति भी

> अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत ने क्षेत्रीय शांति के खतरों पर कोई चर्चा नहीं की, बल्कि अमेरिका में खालिस्तानी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। क्या यह एक रणनीतिक चूक थी?

काफी अच्छी है। अत्यधिक खनन, मछली पकड़ने और अपने बंदरगाह ग्वादर को मजबूत करने में पाकिस्तानी सेना के साथ उसकी मिलीभगत भी उन कारकों में से एक है, जिसने खनिज-समृद्ध बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह को जन्म दिया है।

तुलसी गबार्ड की यात्रा का अघोषित एजेंडा भारत और अमेरिका के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक हिस्सा हो सकता है, जो कि राष्ट्रपति जो बाइडन के पूर्ववर्ती शासनकाल के दौरान साझा की जाने वाली सूचनाओं की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है।

पाकिस्तान में भी जल्द ही इतिहास दोहराया जा सकता है और उसका और अधिक विखंडन हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही भारत के लिए और भी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं।

हालांकि, इस खतरे का सामना करने के लिए भारतीय प्रतिष्ठान को भारतीय उद्योगों के गैर-सरकारी खिलाड़ियों से मुक्त होना होगा। इस पृष्ठभूमि में, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वर्तमान नौकरशाही-संचालित दृष्टिकोण में उसके क्षितिज पर मंडरा रहे खतरों से निपटने के लिए गंभीरता से तैयारी करने की बहुत कम तैयारी है।

मोदी द्वारा अपनी पार्टी के अनुभवी नेताओं को हटाकर सरकार का संचालन कुछ चुनिंदा वफादार नौकरशाहों को सौंपने के प्रयोग से, जिनमें से कई कैबिनेट पदों पर आसीन हैं, न केवल उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, बल्कि देश के महत्वपूर्ण हितों को भी चोट पहुंची है।

इससे उनकी सरकार राजनीतिक रूप से पहले ही कमजोर हो चुकी है। हाल ही में हथकड़ी लगे भारतीयों को भारत लाए जाने पर वे पहले ही राष्ट्रीय शर्म का कारण बन चुके हैं। इसे भारतीय विदेश मंत्रालय और मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले भारतीय मीडिया के एक वर्ग द्वारा बार-बार उचित ठहराया जा रहा है। यह पता नहीं है कि मोदी को तुलसी को प्रयाग से प्राप्त पवित्र गंगा जल के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का मार्गदर्शन करने की सलाह किसने दी।

पूंजीवादी व्यवस्था का संकट : क्या मार्क्स की भविष्यवाणी सच हो रही है ?

-धर्मेन्द्र आज़ाद

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। 2024 से ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट, बेरोज़गारी में वृद्धि और आर्थिक असमानता की गहराई ने पूंजी वाद की नींव को हिला दिया है। दशकों तक यह प्रचारित किया गया कि पूंजी वाद का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आज वही व्यवस्था अपने अंतर्विरोधों में उलझ गई है।

दुनिया भर में उत्पादन तो हो रहा है, परंतु मांग कम हो रही है। वस्तुएँ उपलब्ध हैं, पर उन्हें खरीदने की शक्ति आम जन के पास नहीं है। यह वह संकट है जिसकी भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स ने उन्नीसवीं सदी में की थी। उन्होंने कहा था कि पूंजीवाद केवल उत्पादन को बढ़ाता है, उपभोग को नहीं। क्योंकि श्रमिकों को उनके श्रम का पूरा मूल्य नहीं दिया जाता, वे उपभोग करने की स्थिति में नहीं होते। उत्पादन के साधनों पर कुछ मुट्ठीभर पूंजीपतियों का स्वामित्व और श्रमिक वर्ग की खरीदने की शक्ति में कमी – यही विरोधाभास आर्थिक संकटों का कारण बनते हैं।

मार्क्स के 'अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत' के अनुसार, पूंजीपति श्रमिक को केवल जीवित रहने लायक वेतन देता है, जबकि शेष मुनाफ़ा अपनी जेब में डाल लेता है। 2024 की Oxfam रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 1% आबादी के पास वैश्विक संपत्ति का 46% हिस्सा है, जबकि सबसे गरीब 50% आबादी के पास मात्र 2%। भारत में जहाँ करोड़ों लोग गरीबी और बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ उद्योगपति अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ा चुके हैं।

"जब उत्पादन बढ़ रहा हो लेकिन भूख भी बढ़े — तो समझिए व्यवस्था बीमार है।"

इस विश्लेषणात्मक लेख में जानिए कैसे पूंजीवादी व्यवस्था अपने ही अंतर्विरोधों में फँस चुकी है और क्यों समाजवाद आज पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है।

पूंजीवादी व्यवस्था मेहनत को नहीं, पूंजी को प्राथमिकता देती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बढ़ती बेरोज़गारी है। तकनीकी विकास और ऑटोमेशन का प्रयोग उत्पादन में लागत घटाने और मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए होता है, न कि श्रमिकों की सुविधा के लिए। 2024 के अंत तक वैश्विक बेरोज़गारी दर 8% और भारत में 10% से ऊपर पहुँच गई। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आमदनी में 20% की गिरावट आई, वहीं महंगाई लगातार बढ़ रही है।

पूंजीवाद का चरम विरोधाभास यह है कि लाखों मकान खाली पड़े हैं, फिर भी करोड़ों लोग बेघर हैं। गोदामों में अन्न भरा पड़ा है, लेकिन भूख से लाखों लोग पीड़ित हैं। यह सिद्ध करता है कि पूंजीवाद का उद्देश्य समाज की जरूरतों की पूर्ति नहीं, बल्कि मुनाफ़ा है। जब मुनाफ़ा नहीं होता, तो उत्पादन रुक जाता है और श्रमिकों को बेरोज़गार कर दिया जाता है।

राज्य की भूमिका भी इस शोषण में संलिप्त है। जैसा कि मार्क्स ने कहा था – "आधुनिक राज्य पूंजीपति वर्ग की कार्यकारी समिति मात्र है।" आज की सरकारें पूंजीपतियों के हित में काम कर रही हैं। IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के दबाव में सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो रहा है – रेलवे, बैंकिंग, रक्षा और तेल क्षेत्र कॉर्पोरेट हाथों में बेचे जा रहे हैं। दूसरी ओर, आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, जबकि बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दी जा रही है।

यह स्पष्ट है कि पूंजीवादी व्यवस्था में धन और संसाधनों का संकेंद्रण और आय असमानता जैसी समस्याएँ अंतर्निहित हैं। इनका समाधान पूंजीवाद के भीतर नहीं, बल्कि समाजवाद में निहित है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है और श्रम का मूल्यांकन न्यायसंगत ढंग से किया जाता है। संसाधनों का वितरण समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को मिटाया जा सकता है।

लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने यह सिद्ध किया कि समाजवाद केवल एक विचार नहीं, बल्कि व्यवहार में कारगर व्यवस्था है। मात्र 30 वर्षों में सोवियत संघ ने एक पिछड़े देश को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बना दिया। 1950 तक उसकी औद्योगिक वृद्धि दर पूंजीवादी देशों से अधिक थी। परंतु 1956 में निकिता सेरगेयेविच ख्रुश्चेव के सत्ता में आने के बाद समाजवादी प्रणाली को भीतर से

> गहराते आर्थिक संकट, बेरोज़गारी और सामाजिक असमानता के दौर में क्या समाजवाद ही अंतिम समाधान है? एक विचारोत्तेजक विश्लेषण जो वर्तमान और भविष्य — दोनों पर सवाल उठाता है।

कमजोर किया गया। उसने 'शांति सह-अस्तित्व' की नीति अपनाई और धीरे-धीरे मार्क्सवादी सिद्धांतों से दूर जाकर समाजवाद को बाजारवादी दिशा में धकेल दिया। इसके परिणामस्वरूप समाजवाद के असली समर्थकों को खत्म कर दिया गया और अंततः पूंजीवादी पुनर्स्थापना हो गई।

यह घटना समाजवाद की विफलता नहीं थी, बल्कि उसे भीतर से नष्ट किए जाने का नतीजा थी। पूंजीवाद समर्थकों का यह तर्क कि समाजवाद असफल रहा है, अधूरा और भ्रामक है। असल में, समाजवाद ही वह व्यवस्था है जो मेहनतकश जनता के हित में काम करती है। इसमें उत्पादन समाज की आवश्यकताओं के लिए होता है, न कि मुनाफ़े के लिए।

मार्क्स ने कहा था कि "मजदूर वर्ग ही इतिहास का वास्तविक निर्माता है।" पूंजीवाद अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह अंत स्वतः नहीं होगा। इसके लिए संगठित मजदूर वर्ग को खड़ा होना पड़ेगा और समाजवादी क्रांति को दिशा देनी होगी। समाजवाद ही एकमात्र व्यवस्था है जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी सुविधाएं सभी के लिए सुलभ होती हैं, न कि किसी कंपनी के लाभ का साधन।

अब सवाल यह नहीं है कि समाजवाद संभव है या नहीं, बल्कि यह है कि पूंजीवादी संकट से बाहर निकलने के लिए समाज इसे कब और कैसे अपनाता है। मार्क्स ने स्पष्ट किया था कि पूंजीवाद का अंत अवश्यंभावी है और समाजवाद ही उसका उत्तराधिकारी होगा। आज की वैश्विक परिस्थितियाँ इस भविष्यवाणी को सच करती दिख रही हैं। पूंजीवादी व्यवस्था न केवल असफल हो चुकी है, बल्कि अब वह अपने ही अंतर्विरोधों से जूझ रही है और ढहने के कगार पर खड़ी है।

****

भारत का इतिहास और हिंदुत्व की धारणा : एक विश्लेषण

-सुरैना अय्यर

सुरैना अय्यर

अध्याय 18: महान दक्खनियों में से अंतिम

शिवाजी और औरंगजेब का संघर्ष

भारत के दक्षिण क्षेत्र में शिवाजी भोंसले का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ और वह बीजापुर सल्तनत के अधीन एक महत्वपूर्ण योद्धा बने। उनके दादा, मालोजी भोंसले, ने अहमदनगर सल्तनत के अधीन कार्य किया था।

दक्षिण भारत के इतिहास में शिवाजी, हैदर अली और टीपू सुल्तान का योगदान अद्वितीय रहा है। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष किया और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनके बाद, हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। 18वीं सदी के अंत तक, अंग्रेजों ने धीरे-धीरे दक्खन पर नियंत्रण कर लिया, जिससे 1857 के विद्रोह तक भारत में औपनिवेशिक शासन मजबूत होता चला गया।

शिवाजी ने अपने पिता शाहजी भोंसले के मार्गदर्शन में कई किलों पर कब्जा किया और बीजापुर के सुलतान के खिलाफ विद्रोह किया।

शिवाजी का संघर्ष मुख्यतः मुगलों के साथ था, विशेषकर औरंगजेब के साथ। औरंगजेब, जो एक कट्टर मुसलमान था, ने हिंदू धर्म के प्रति अपनी नफरत को बढ़ावा दिया, जिससे शिवाजी को और भी अधिक समर्थन मिला। शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई किलों पर कब्जा किया, जिसमें गिंगी और जावली शामिल थे।

शिवाजी का साम्राज्य और उनकी रणनीतियाँ

शिवाजी ने दक्षिण में एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने किलों का निर्माण किया और अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। उनकी रणनीतियों में गेरिल्ला युद्ध का उपयोग शामिल था, जिससे उन्होंने मुगलों को कई बार हराया। शिवाजी ने अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के लोगों को शामिल किया और एक बहु-सांस्कृतिक शासन की स्थापना की।

शिवाजी और औरंगजेब का संघर्ष भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। 17वीं शताब्दी में, शिवाजी ने मुगलों और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिससे वे एक कुशल योद्धा और कुशल प्रशासक बने। उनका राज्याभिषेक 1674 में हुआ, लेकिन हिंदू रूढ़िवादियों ने उनकी क्षत्रिय पहचान पर सवाल उठाया। शिवाजी के बाद, दक्खन में सत्ता संघर्ष जारी रहा, जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला।

उनकी मां जीजाबाई और दादोजी कोंड देव ने उनके पालन-पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी ने अपने साम्राज्य में मुस्लिम अधिकारियों को भी शामिल किया, जो उनकी उदारता को दर्शाता है।

शिवाजी का राज्याभिषेक और हिंदू रूढ़िवाद

1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन इस पर हिंदू रूढ़िवादियों ने आपत्ति जताई। उन्होंने शिवाजी को क्षत्रिय मानने से इनकार किया, जिससे शिवाजी को एक पुरोहित की मदद से अपने वंश को प्रमाणित करना पड़ा। यह घटना दर्शाती है कि कैसे धार्मिक पहचान ने राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित किया।

शिवाजी के बाद का काल

शिवाजी की मृत्यु के बाद, उनके बेटे शम्भाजी ने गद्दी संभाली,

शिवाजी का उदय केवल एक शासक की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता और संघर्ष का प्रतीक है। उनकी युद्ध रणनीतियों और प्रशासनिक कौशल ने उन्हें एक महान नेता बनाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, दक्खन की राजनीति में औरंगजेब, मराठा उत्तराधिकारी, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच लगातार टकराव चलता रहा। आखिरकार, अंग्रेजों ने इन संघर्षों का लाभ उठाकर पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया।

लेकिन उनके शासन में कई चुनौतियाँ आईं। औरंगजेब ने शम्भाजी को पकड़ लिया और मार डाला। इसके बाद, राजाराम ने गद्दी संभाली, लेकिन उनके शासन में भी संघर्ष जारी रहा।

हैदर अली और टीपू सुल्तान का उदय

हैदर अली, जो पहले एक अधिकारी थे, ने मैसूर में सत्ता संभाली। उन्होंने अपने प्रशासन में ब्राह्मणों को शामिल किया और एक मजबूत शासन स्थापित किया। टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र, ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े।

दक्षिण में अंग्रेजों का उदय

18वीं सदी के अंत में, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत की। उन्होंने विभिन्न राज्यों के साथ गठबंधन किए और धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया।

1857 का विद्रोह

1857 में, जब उत्तर भारत में विद्रोह हुआ, दक्षिण भारत में स्थिति अलग थी। दक्षिण भारतीय हिंदू विद्रोह में शामिल नहीं हुए, जो कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है।

भारत का इतिहास एक जटिल tapestry है, जिसमें विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और राजनीतिक संघर्षों का समावेश है। शिवाजी, हैदर अली, और टीपू सुल्तान जैसे व्यक्तित्वों ने दक्खन के इतिहास

भारत के दक्षिण क्षेत्र का इतिहास सत्ता, संघर्ष और रणनीति की कहानियों से भरा हुआ है। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान, उनके गुरिल्ला युद्ध कौशल और प्रशासनिक सुधारों ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। उनके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः औपनिवेशिक शक्तियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। यह पुस्तक दक्षिण के महान योद्धाओं की प्रेरणादायक गाथा प्रस्तुत करती है।

को आकार दिया, जबकि अंग्रेजों ने धीरे-धीरे पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित किया। यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान ने राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित किया और कैसे विभिन्न शक्तियों ने एक-दूसरे के खिलाफ संघर्ष किया।

इस प्रकार, भारत का इतिहास न केवल एक संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह एक बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक समाज की कहानी भी है, जो समय के साथ विकसित होता रहा है।

****

महाबोधि मंदिर प्रबंधन: बौद्धों के साथ ऐतिहासिक अन्याय !

-प्रशांत गौतम

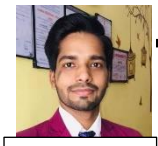

प्रशांत गौतम

हिंदू कट्टरपंथी जो मुस्लिम शासकों पर भारत में हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आरोप लगाते हैं, उन्हें हमारे इतिहास पर फिर से नज़र डालने की ज़रूरत है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में मुस्लिम शासन के आगमन से पहले हिंदू राजाओं और धार्मिक समूहों द्वारा नष्ट किए गए बौद्ध स्थलों की संख्या मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए हिंदू मंदिरों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। क्या यह विडंबना नहीं है कि एक तरफ़ ये हिंदू कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों के विनाश पर हंगामा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ़ वे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ किए गए उसी अन्याय को अनदेखा करते हैं?

क्या भारत सच में 'बुद्ध की भूमि' होने का दावा कर सकता है? महाबोधि मंदिर, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, आज हिंदू प्रभाव में है। यह किताब इस ऐतिहासिक अन्याय की गहरी पड़ताल करती है और पूछती है—क्या बौद्धों को उनके ही धर्मस्थल का पूरा अधिकार नहीं मिलना चाहिए?

बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर इसका सबसे बड़ा सबूत है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने लगभग 2,500 साल पहले बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यह बौद्धों के लिए उतना ही पवित्र है जितना हिंदुओं के लिए राम मंदिर या मुसलमानों के लिए मक्का। फिर भी, दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि आज इस बौद्ध मंदिर में हिंदुओं की संख्या अधिक है जो अपने धार्मिक अनुष्ठानों से इसे कलंकित करते हैं।

महाबोधि मंदिर का इतिहास गवाह है कि कैसे इस पवित्र बौद्ध स्थल को जबरन हिंदू प्रभाव में लाया गया। सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन समय के साथ हिंदू महंतों और पंडितों ने इस पर नियंत्रण कर लिया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी सरकार बौद्धों के अधिकारों को बहाल करने में विफल रही और

बौद्ध धर्म भारत में जन्मा, लेकिन क्या उसे यहाँ न्याय मिला? महाबोधि मंदिर, जो बौद्धों के लिए उतना ही पवित्र है जितना मक्का मुसलमानों के लिए, हिंदू प्रशासन के अधीन क्यों है? यह पुस्तक धार्मिक और ऐतिहासिक अन्याय पर एक साहसिक सवाल उठाती है।

बोधगया मंदिर अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के तहत:

- मंदिर का प्रशासन बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) को सौंपा गया।

- इस आठ सदस्यीय समिति में चार हिंदू और चार बौद्ध शामिल हैं।

- मंदिर का मुख्य पुजारी (महंत) हमेशा हिंदू ही रहेगा।

- गया जिले के जिला मजिस्ट्रेट स्वतः ही इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, और यदि वह

हिंदू नहीं हैं, तो सरकार एक हिंदू अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी।

यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए गए इस स्थान पर बौद्ध धर्म से कहीं ज़्यादा हिंदू रीति-रिवाज़ किए जाते हैं। पिंडदान, हवन और दूसरे ऐसे कर्मकांड किए जाते हैं जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं। सवाल यह है कि क्या यह वही भारत है जो खुद को 'बुद्ध की धरती' होने पर गर्व करता है? क्या यह वही देश है जहाँ के प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह कहते हैं कि "मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ"?

बौद्धों ने बार-बार इस अन्याय के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन हर बार हिंदू संस्थाओं ने उन्हें दबाने का प्रयास किया है:

महाबोधि मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों का प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि कैसे बौद्ध स्थलों पर हिंदू प्रभाव बढ़ता गया।

- 1891: श्रीलंका के बौद्ध संत अनागारिक धर्मपाल ने पहली बार मंदिर को बौद्धों को सौंपने की मांग उठाई, लेकिन हिंदू भिक्षुओं ने इसे अस्वीकार कर दिया।
- 1922: गया कांग्रेस अधिवेशन में यह मुद्दा उठाया गया, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला।
- 1949: आजादी के बाद भी गांधीजी का वादा टूटा और सरकार ने बीटीएमसी की स्थापना की।
- 1992, 1995, 2017: बौद्ध भिक्षुओं ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन किए, मंदिर पर हिंदू नियंत्रण बनाए रखा।
- 2024: अखिल भारतीय बौद्ध मंच ने एक बार फिर आंदोलन छेड़ा, बोधगया मंदिर अधिनियम को निरस्त करने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनदेखी की।
- बौद्ध भिक्षुओं और संगठनों की मांगें स्पष्ट हैं:
- बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द किया जाना चाहिए।
- बीटीएमसी का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण केवल बौद्ध समुदाय को दिया जाना चाहिए।
- महाबोधि मंदिर को हिंदू रीति-रिवाजों से मुक्त किया जाना चाहिए।
- बौद्ध स्थलों को हिंदू महंतों के नियंत्रण से हटाया जाना चाहिए।

महाबोधि मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। सच तो यह है कि लंबे समय तक हिंदू शासकों ने हजारों बौद्ध मठों और स्तूपों को नष्ट कर दिया।

बौद्धों द्वारा पूछा जा रहा प्रश्न यह है कि यदि किसी अन्य धर्म के अनुयायियों को हिंदू मंदिरों में प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए जाते तो फिर महाबोधि मंदिर पर हिंदुओं का नियंत्रण क्यों है?

सरकार को इस विवाद का संतुलित समाधान निकालना होगा अन्यथा हम बुद्ध की भूमि से उनकी विरासत को मिटाने का पाप करते रहेंगे।

अंत में, हिंदू समुदाय के सभी सदस्यों के लिए एक प्रश्न: यदि महाबोधि मंदिर बौद्धों का है, तो क्या इसे पूरी तरह से बौद्धों को नहीं सौंप दिया जाना चाहिए?

****

लेखक : मीडिया मैप के मुख्य सह-संपादक है।

डॉ अंबेडकर की वैचारिक यात्रा

-नरेंद्र कुमार

डॉ अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक यात्रा ब्राह्मणवाद के कर्मकांडी तथा घृणित जाति-व्यवस्था के खिलाफ मुखर आवाज के रूप में शुरू की। फ्रांसीसी क्रांति तथा पश्चिमी लोकतंत्र से प्रभावित अंबेडकर की समझ थी कि भारत में ब्राह्मणवाद की जड़ों को नष्ट कर पूंजीवाद एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करेगा। इसी समझ के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा भारतीय पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रति या तो वे उदासीन रहे या कई अर्थों में उनका समर्थन भी किया।

ब्राह्मणवाद जिसकी जड़ें भारतीय भूमि- संबंध यानी कि अर्ध-सामंती सामाजिक संबंधों से रक्षित था। इसकी गहराई में जाकर विचार करने की कोशिश वे नहीं करते हैं। उस दौर में भारत के 90% अछूत जातियां जो बंधुआ मजदूर, दस्तकार करीब किसान व सफाई कर्मी थे जो पूंजीवादी व सामंती आर्थिक तथा सामाजिक उत्पीड़न की पीड़ा झेल रहे थे। उनकी मुक्ति की लड़ाई के लिए आवश्यक था कि पूंजीवादी व सामंती भू संबंध को ध्वस्त कर उन्हें साधनों का मालिक बनाया जाए। लेकिन अंग्रेज प्रशासन तथा

डॉ भीम रॉव अम्बेडकर (1891 - 1956)

पूंजीपतियों ने इसे सुरक्षित रखा। सामंती भू -संबंध व सामंतों ने इन मेहनतकश अछूत जातियां को अपने पैरों तले दबाए रखने में ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा उसके प्रशासन से भरपूर सहयोग पाया। बदले में टैक्स के रूप में और मजदूर वर्ग को दबाए रखने में सामंती समाज ने उनकी मदद की।

उनकी मुक्ति के लिए संघर्ष की आवाज विभिन्न क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही उठाया गया जिसमें अंबेडकर की भागीदारी नहीं रही ,जबकि ठीक इसी दौर में भगत सिंह ने अछूत तथा सांप्रदायिकता की समस्या के समाधान के तौर पर सामंती शक्तियों के द्वारा मेहनतकशों के शोषण तथा पूंजीपतियों के द्वारा कारखाने में मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज को प्राथमिकता देकर उठाया।

भगत सिंह ने स्पष्ट तौर पर बात रखी कि सामंतवाद और भारतीय पूंजीपति साम्राज्यवादी शक्तियों से संरक्षित हैं। भगत सिंह से कहीं अधिक पढ़ने और विद्वान होने के बावजूद पूंजीवादी लोकतंत्र के प्रति मोह ग्रस्त होने के कारण वे जमीनी हकीकत से नहीं जुड़ पाए। इसीलिए आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष भी उनकी सीधी भागीदारी नहीं हुई और न ही सामंती

शक्तियों के खिलाफ उन्होंने ने आवाज उठाया।

कुछेक जगह कुएं और तालाब के पानी के उपयोग के तौर पर सुधारात्मक आंदोलन उन्होंने अवश्य चलाया । यदि इस आंदोलन को भी आगे वे बड़े पैमाने पर संगठित करते, तो जन आंदोलन के रूप में सामंतवाद विरोधी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता। लेकिन यह भी सिंबॉलिक बनकर ही रह गया।

भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस मायने में उन्हें भारतीय पूंजीवादी लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में याद किया जाना चाहिए। पूंजीवादी लोकतंत्र के संरक्षक होने के कारण ही तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन पर नेहरू सरकार के द्वारा भयंकर दमन के समय वे चुप रहे।

लेकिन जीवन के अंतिम समय में भारतीय पूंजीवादी लोकतंत्र से उनका मोह भंग हो गया और अपनी निराशा की स्थिति में उन्होंने अपने कई भाषणों में यह वक्तव्य दिया कि मेहनतकश दलित समाज की मुक्ति का रास्ता समाजवाद से निकलेगा। इस रूप में अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन विश्व दृष्टिकोण के तौर पर विश्व के अन्य पूंजीवादी देशों के लिए उन्होंने पूंजीवादी लोकतंत्र की व्यवस्था को ही सही ठहराया। भारत की स्थिति ने उन्हें भले ही भारतीय दलित समाज की मुक्ति के लिए समाजवाद के पक्ष में खड़े होने के लिए बाध्य किया, लेकिन वह अंतिम समय तक पूंजीवादी लोकतंत्र के पक्षधर रहे। इस मायने में एक विचारक के तौर पर उनकी तुलना झॉ-पॉल सार्त्र से करना उचित होगा।

क्या डॉ. अंबेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाना चाहिए, या उनके वैचारिक अंतर्विरोधों पर भी चर्चा होनी चाहिए? पूंजीवादी लोकतंत्र के समर्थक होने के बावजूद, जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने समाजवाद की ओर रुख किया। भगत सिंह और मार्क्सवादी आंदोलन की तुलना में उनका दृष्टिकोण कितना अलग था? यह लेख इन्हीं सवालों पर रोशनी डालता है।

झॉ-पॉल सार्त्र ने अस्तित्ववाद के सिद्धांतकार के रूप में साम्राज्यवाद के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठायी। मध्य वर्ग तथा निम्न पूंजीवादी वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी वैचारिक यात्रा के अंतिम दौर में वह समाजवाद के समर्थक बने और अंत में मार्क्सवाद लेनिनवाद को भी अपनी सीमाओं में स्वीकार किया। यह तथ्य उन्हें मार्क्सवाद लेनिनवाद का समर्थक तो बनाता है, लेकिन विचारक के तौर उन्हें अस्तित्ववादी दार्शनिक के रूप में ही याद किया जाता है। जाति उत्पीड़न को मुखर हो कर उठाने तथा मार्क्सवाद व समाजवाद का समर्थन करने के लिए हम अंबेडकर का अभिनंदन करते हैं। लेकिन इसी पक्ष को सामने रखकर उनके पूरे जीवन काल की रचनाओं के अंतर्विरोधों तथा पूंजीवादी लोकतंत्र की पक्षधरता पर चुप नहीं रहना चाहिए। उसकी भी उतनी ही निर्माता के साथ आलोचना की जानी चाहिए। आज के दौर में यह इसलिए भी आवश्यक है की बहुत सारे संगठन उनके समाजवाद के समर्थन वाले पक्ष को सामने रखकर उनके पूरे जीवन काल की रचना तथा व्यवहार पर चुप्पी साध लेते हैं।

(लेखक मार्क्सवाद के अध्येता, व विचारक व सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हैं.)

अनोखा बोझ

लेखक दिनेश वर्मा, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना समय लेखन को समर्पित किया और वर्ष 2016 में उनकी पहली किताब 'माई टाइम्स माई टेल्स' में प्रकाशित हुई जो 27 कहानियों का संग्रह है। पुस्तक का हिंदी अनुवाद "मेरे समय की मेरी कहानियाँ" के रूप में हुआ। प्रस्तुत कहानी उसी संग्रह से ली गयी है।

- संपादक

****

"अरे यह कहाँ गायब हो गया? मैं ने अभी इसी पलंग पर रखा था कुछ सेकंड पहले," वह बेचैनी से बडबडाई और पागलों की तरह उसे ढूँढना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने उसे वहाँ ठीक से ढूंढा जहाँ उन्होंने उसे अपनी याददाश्त में रखा था। वहाँ जब नहीं मिला तो और सब जगह भी बार बार ढूंढा और जब बार बार देखने के बाद भी कहीं नहीं मिला तो वह बुरी तरह से घबरा गईं। यह बात तब की है जब वह ड्रेसिंग टेबल के बडे शीशे के सामने खडें होकर अपनी बडी बेटी के विवाह स्थल पर प तैयार हो रही थीं। उनकी बड़ी बहन भी उसी कमरे में तैयार हो रही थी जो अब सब कुछ छोड़कर उसको ढूँढ़ने में लग गईं। पहुँचने के लिए

"तुम्हें ठीक से याद है, लीना, कि तुमने उसे पलंग पर ही रखा था? तुम फिर ठीक से याद करने की कोशिश करो। हो सकता है तुमने कहीं और रख दिया हो।" रबीना लीना की बड़ी बहन थी और वह कोने कोने में झांक कर उसे ढूँढ रही थीं और यही कहती जा रही थीं कि "लीना, तुम ठीक से याद करो कि तुमने उसे कहाँ रखा था।"

"नहीं दीदी, नहीं," लीना ने जवाब दिया, "मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है। मैं ने उसे अपनी साड़ी को ठीक से लपेटते समय अपनी बाई तरफ रख दिया था ताकि मैं साड़ी ठीक कर संकू। मैंने उसे पलंग के उस कोने पर रखा था जहाँ ड्रेसिंग टेबल है। लेकिन जब मैं अपनी साड़ी ठीक करके उसे उठाने के लिए झुकी तो वह वहाँ नहीं था।"

"अजीब बात है! बड़ी अजीब बात है! उसे क्या ज़मीन निगल गई?" रबीना ने झुंझलाते हुए कहा और फिर उसे ढूँढ़ने में व्यस्त हो गईं। उन्होंने उसे हर उस स्थान पर ढूंढ डाला जहाँ उसके होने कि संभावना थी। लेकिन सारे प्रयत्न व्यर्थ गए।

इस बीच लीना के पति और परिवार के और सदस्य लीना को जल्द से जल्द आने के लिए बार बार टेलीफोन कर रहे थे। आखिर वह दुल्हन की माँ थीं और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहाँ उनका होना आवश्यक था। उधर दूर सड़क पर बारात आतिशबाज़ी और ढोल ताशों की आवाज़ के साथ तेज़ी से विवाह स्थल की ओर बढ़ रही थी। और, यहाँ घर पर, लीना और रबीना के साथ उसकी छोटी बेटी और उसकी सहेली सोनम भी उस हार को ढूँढ़ने में पागलों कि तरह लगे हुए थे। उन्होंने कमरे का कोना कोना छान मारा, सारी चीज़े हटा कर देख लिया, पर वह हार ऐसे गयाब हो गया था जैसे गधे के सिर से सींग।

लीना की लगातार देरी से घबरा कर उस का बेटा उस के भतीजे के साथ दौड़े दौड़े आए ताकि वह लीना को जल्द से जल्द अपने साथ विवाह स्थल पर ले जाएं। लेकिन वे जैसे ही कमरे में घुसे यह भूल गए कि वे वहाँ क्यों आए थे और हार को ढूँढ़ने में लग गए। आखिर हीरे का हार कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस घटना ने वातावरण को अच्छा खासा रहस्यपूर्ण बना डाला और लोग तरह तरह की बाते करने लगे। कमरे में कौन कौन गया था? कौन अंदर गया और कौन बाहर आया? घर का कोई नौकर चाकर कमरे में आया था क्या? इस प्रकार के अनेको प्रश्न वातावरण में घूम रहे थे हालाँकि इन सब सवालों का एक ही उत्तर मिल रहा था और वह यह कि परिवार के घनिष्ठ सदस्यों के अलावा कमरे में न कोई गया था न आया था। ऐसी ही कानाफूसी के बीच लीना विवाह स्थल पर पहुँच गईं और यह प्रयत्न करती रहीं कि इस नुकसान का प्रभाव उन के चेहरे पर न आने पाए। समय की

नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने अतिथियों का स्वागत बड़ी हिम्मत के साथ किया। विवाह स्थल पर जिन मेहमानो को हार के बारे में पता चला नाश्ता करते करते वे आगे होने वाली कार्यवाही के बारे में सोच रहे थे। कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को तुरन्त निरस्त कर दिया गया। इस के अतिरिक्त अन्य संभव कार्यवाहियों के विषय में भी विचार किया गया। एक बात तो बिलकुल साफ थी वह यह कि इतनी गहराई से छान बीन के बाद हार का उस कमरे में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर वह अगर वहाँ नहीं था तो अवश्य कोई न कोई उसे लेकर ही गया होगा। लेकिन कौन? कोई ऐसा व्यक्ति कमरे में गया ही नहीं जिस पर शक किया जा सकता। केवल लीना की छोटी बेटी की सहेली सोनम ही थी जो बाहर की थी और जो कमरे में हार ढूँढ़ने में मदद कर रही थी। शक की सुई कुछ क्षण सोनम पर रुकी जरुर लेकिन फिर उसे भी नकार दिया गया क्योंकि वह परिवार के सदस्य जैसी ही थी और उस पर शक करने का कोई मतलब ही नहीं था।

लीना की चचेरी बहन अवन्तिका को जब इस नुकसान के बारे में पता चला तो औरों की तरह उनको भी धक्का लगा। अवन्तिका एक बहुत समझदार, गुणी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की महिला थीं और दूसरी महिलाओं के लिए एक उदहारण थी। यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने भी लीना को, समय की नाजुकता को देखते हुए, स्वाभाविक ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया।

अवन्तिका स्वभाव से बहुत मिलनसार रही है और जब से वह विवाह स्थल पर पहुँची थीं तब ही से इधर उधर घूम फिर कर मित्रों और रिश्तेदारों से गपशप करती रही थीं। लेकिन इधर उधर घूमने में न जाने क्यों उन्हें परेशानी सी हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ अपने ऊपर उठा कर चल रही हों। क्योंकि बारात गेट के पास पहुँचने वाली थी वह भीड़ से हट के एक ऐसे स्थान पर अपनी बहन और भतीजों के साथ पहुँची जहाँ थोड़ा अंधेरा सा था ताकि वह अपनी साड़ी ठीक से संभाल सकें। असल में उन की साड़ी का पल्लू बार बार कंधे पर डालने के बाद भी एक तरफ को गिरे जा रहा था। पहले भी उन्होंने अपनी परेशानी का कारण ढूँढ़ने का प्रयत्न किया था और साड़ी को पूरी तरह देख डाला, मगर फिर भीड़ भाड़ के कारण जल्दी से वापस आ गई थी। दोबारा उसकी छानबीन करने कि ज़रुरत तब पड़ी जब उस साड़ी को पहने उन का चलना फिरना मुश्किल हो गया। और अब उस अंधेरे से कोने में छानबीन के बाद वह चीज़ हाथ लगी जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी।

साड़ी का वह किनारा जहाँ काफी पेचदार बनावट के साथ जाली का काम किया हुआ था वहाँ लम्बी धातु की कोई ऐसी चीज़ अटकी हुई थी जिसे बगैर साड़ी को उधेड़े पल्लू से निकाल पाना असंभव था। साड़ी भी अच्छी खासी महंगी थी। लेकिन उसे साड़ी से निकलना तो था ही। लिहाज़ा उसे साड़ी से अलग करने का कार्य आरंभ हुआ। बड़ी सावधानी के साथ काफी देर की मेहनत के बाद उसे निकाल पाने में सफल हुए और जब वह धातु की वस्तु निकल कर बाहर आई तो उन सबको हँसी रोकना मुश्किल हो गई। अवन्तिका की आँखों से तो प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। यह वही हीरों का हार था जो लीना के कमरे से गायब हो गया था।

अपनी भावनाओं पर काबू करके अवंतिका विवाह के गेट पर चलकर पहुँची जहाँ लीना दुल्हे के स्वागत की तैयारी में जुटी हुई थीं। यह वह समय था जब बारात गेट के अंदर घुस गई थी और बारातियों का नाच ढोल ताशों के बीच अपनी चरमसीमा पर था। अवन्तिका ने धीरे से लीना के कान में मधु घोल दिया और फिर उनकी खुशी से चमकते चेहरे को निहारती रहीं। कुछ घंटे पहले ही लाखों के उस नुकसान ने लीना का मानों खून चूस लिया था।

यह रहस्यमय गाथा चारों तरफ फैलती गई। जिन लोगों को भी इस बारे में मालूम था वे भगवान द्वारा खेले गए उस अद्भुत मज़ाक पर कहकहे लगा रहे थे। अब बात बिलकुल साफ थी। जब अवन्तिका कमरे के साथ वाले बाथरूम से निकल कर बाहर जा रही थी जहाँ लीना साड़ी बदल रही थी तब यह हार साड़ी में सिमट गया जिसे लेकर अवन्तिका सारे विवाह स्थल पर घूमती रहीं थीं

****

पुस्तक समीक्षा

पाकिस्तान की दिशाहीन राजनीति

-जगदीश गौतम

सैयद नूरुज्जमां

(यह आलेख सैयद नूरुज्जमां की नवीनतम पुस्तक से लिया गया है। द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ के पूर्व उप संपादक, जो इनका कार्यभार संभालते थे 21 साल से ज़्यादा समय तक अख़बार के संपादकीय पेज पर काम किया। उन्होंने एक लोकप्रिय लेख लिखा 2013 में अपनी सेवानिवृत्ति तक वे पाकिस्तान पर साप्ताहिक स्तंभ लिखते रहे।

अंग्रेजी से अनुवादित और फरवरी में तहलका पत्रिका में प्रकाशित 2017, की एक झलक प्रदान करने के लिए मीडियामैप में पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुस्तक में चर्चित मुद्दे और घटनाएँ।

पाकिस्तान में "लापता" मुद्दा: "मैं कब एक फाइल बन जाऊंगा"

पाकिस्तान के संदर्भ में 4-7 जनवरी (वर्ष 2017) की अवधि महत्वपूर्ण रही।

यह चुप कराने के लिए अपहरण की खतरनाक रणनीति की याद दिलाता है। बलूचिस्तान में इस्लामाबाद के विरोधियों के खिलाफ इन चार दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खुफिया नेटवर्क ने अपनी मनमानी जारी रखी है।

उदारवादी विचार रखने वाले और अपनी बात कहने में मुखर रहने वाले लोगों पर आतंक का खतरा उनके विचार। नौ ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता, मुख्य रूप से वामपंथी विचारधारा वाले

सोशल मीडिया पर सक्रिय विचारकों में एक पत्रिका संपादक भी शामिल हैं, जो

उन्होंने सरकार की ओर से मिलने वाली

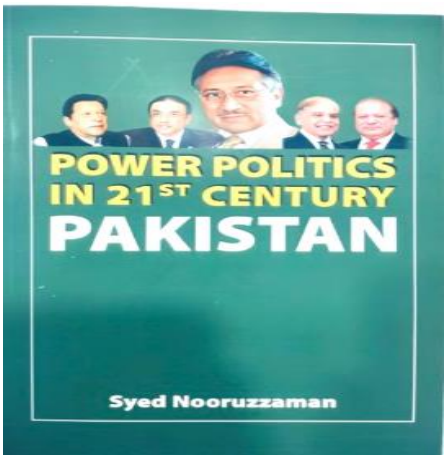

धमकियों की चिंता करने से इनकार कर दिया। खुफिया एजेंसियों को उनके असुविधाजनक विचारों के लिए दंडित किया गया । खुफिया एजेंसियों ने अपहरण का सहारा लिया है।

ये लापता लोग उन्हें वापस लाने के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयासों के बावजूद उनका पता नहीं चल पाया है

उनके परिवारों को ऑनलाइन से जुड़े संपादक सलमान हैदर पाक्षिक पत्रिका तनकीद, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर केंद्रित 6 जनवरी को दो अन्य व्यक्तियों द्वारा अपहरण किए जाने की सूचना मिलने के बाद उनका अपहरण कर लिया गया था।

सक्रिय ब्लॉगर, 4 जनवरी को गायब हो गए। कोई निर्णायक नहीं है इन आवाजों को दबाने के पीछे की ताकतों का सबूत, लेकिन सरकार की खुफिया एजेंसी की ओर उंगली उठाई जा रही है दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इस आरोप से इनकार नहीं किया है।

जो आसानी से चिपक जाता है। 21वीं सदी के पाकिस्तान में सत्ता की राजनीति

85 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (आईएफजे) अपने सहयोगी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) ने कहा है कि मांग की कि सच्चाई सामने लाने के लिए मामले की जांच होनी चाहिए जल्द ही। आईएफजे द्वारा जारी की गई अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जैसा कि अपेक्षित था।

"आईएफजे कार्यकर्ताओं के गायब होने से गंभीर रूप से चिंतित है। पत्रिका के संपादक और ब्लॉगर सलमान हैदर भी इसमें शामिल हैं।

गायब होने की घटनाएं, लोकतंत्र के चैंपियनों को निशाना बनाने की एक खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आलोचनात्मक आवाज़ों के प्रति असहिष्णुता।

ये घटनाएं लोकतंत्र को कमजोर करती हैं और उन लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं जो पत्रकार और ब्लॉगर सहित सभी लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बात व्यक्त करते हैं। आईएफजे ने पाकिस्तान सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया हैदर और अन्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित करें।"

सलमान उनके मित्र और प्रशंसक उन्हें सल्लू कहते थे, जो पत्रकारिता भी पढ़ाते थे फातिमा जिन्ना विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद, मैं 1992 में इस्लामाबाद में कहीं बाहर गया था।

6 जनवरी की शाम को वह अपने दोस्तों के साथ अपनी कार में सवार हुआ। उसकी पत्नी ने उसे कार से बाहर निकाल दिया।

रात 8 बजे तक वापस न आने पर उसे बेचैनी महसूस हुई और उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया चुप हो गई। गड़बड़ी की आशंका होने पर उसने तुरंत उसे सूचित किया रिश्तेदारों ने मामले को पुलिस के संज्ञान में लाया, लेकिन सभी व्यर्थ।

थोड़ी देर बाद उसे अपने सेल फोन पर एक संदेश मिला इस्लामाबाद के बाहरी इलाके से अपनी कार वापस ला रहे थे। कुछ समय पहले एक लेख लिखते समय यह बात चौंकाने वाली थी कि बलूचिस्तान में अपने कुछ दोस्तों के अपहरण पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने आशंका जताई कि एक दिन उनका भी वही हश्र होगा जो उनके दोस्तों का हुआ।

यदि अधिकारियों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया तो वास्तविकताओं के सामने आने की स्थिति में असहमति को सहन करने के लिए तैयार बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत। यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं जो दिखाती हैं कि उन्होंने अपनी आशंकाओं को किस रूप में व्यक्त किया।

कविता की यह पंक्ति, द्विभाषी ऑनलाइन पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित हुई तनकीद: 86 | 21वीं सदी के पाकिस्तान में सत्ता की राजनीति

> यह चुप कराने के लिए अपहरण की खतरनाक रणनीति की याद दिलाता है । बलूचिस्तान में इस्लामाबाद के विरोधियों के खिलाफ इन चार दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खुफिया नेटवर्क ने अपनी मनमानी जारी रखी है।

अभी मेरे दोस्तों के दोस्त 'गायब' हो रहे हैं जल्द ही यह मेरा होगा दोस्तों की बारी और फिर मेरी... जब मैं फ़ाइल बन जाऊँगा कि मेरे पापा अदालत की सुनवाई में लाऊँगा या वह तस्वीर जिसे मेरा बेटा चूमेगा जब एक पत्रकार ने पूछा। तनकीद के कर्मचारी इस घटना से स्तब्ध थे। विकास और अधिकारियों से उसकी खोज करने की अपील की ठिकाना खोजने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली: "तनक़ीद की संपादकीय टीम अपने ही एक सदस्य के लापता होने की खबर सुनकर स्तब्ध हूं: सलमान हैदर, एक प्रसिद्ध उर्दू कवि, एक बड़े दिल वाले संपादक, एक विचारशील विद्वान, और एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता... हैदर एक स्थायी व्यक्ति रहे हैं तनकीद की टीम ने अनुवाद, संशोधन और संपादन में अनगिनत घंटे खर्च किए हैं।

उर्दू लेखों के संपादन के अलावा वह अपना उर्दू ब्लॉग भी लिखते हैं। लगभग छह महीने पहले लिखी गई और उनके द्वारा प्रकाशित की गई भविष्यदर्शी कविता ब्लॉग में उन्होंने अपने दोस्तों के लापता होने की बात कही और भविष्यवाणी की कि हो सकता है, एक दिन उसकी बारी आए।" यह कितना सच था! विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कुछ अन्य "लापता" मामलों के समर्थन में भी अलग-अलग स्थानों पर आयोजन किया गया।

पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जब से ये घटनाक्रम उजागर हुआ है मीडिया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अधिकारी बेपरवाह बने रहे। सलमान के अलावा अन्य लोगों ने भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

व्यापक रूप से चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में अहमद रजा नसीर शामिल हैं, समर अब्बास, असीम सईद और अहमद वकास गोराया। वे या तो के कटु आलोचक होने के कारण उनका अपहरण कर लिया गया है या वे लापता हो गए हैं पाकिस्तान सरकार की नीतियों के कारण सईद और गोराया ने एक लोकप्रिय पार्टी बनाई।

सेना विरोधी फेसबुक पेज मोची। मार्च 2014 में, पत्रकार और लेखक रजा रूमी पर एक चरमपंथी संगठन ने हमला किया क्योंकि उन्होंने उनकी आलोचना की थी।

सरकार द्वारा उग्रवादियों को राज्य की शक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल करना भारत और अन्य पड़ोसियों के बारे में नीति। रूमी उन पर हुए हमले में बच गए, लेकिन पाकिस्तान में रहने का साहस नहीं जुटा सके और चले गए संयुक्त राज्य अमेरिका। 21वीं सदी के पाकिस्तान में सत्ता की राजनीति | 87 रूमी के बाद अब बारी आई 40 वर्षीय महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता सबीन की महमूद की अप्रैल 2014 में हत्या कर दी गई थी। सबीन एक बहस में शामिल थी।

लाहौर विश्वविद्यालय में बलूचिस्तान के लापता लोगों के बारे में मैनेजमेंट साइंसेज (LUMS) में दाखिला लिया, जब उसे मौत के घाट उतार दिया गया।

सत्ता-विरोधी विचार। पाकिस्तान की सत्ता-विरोधी तानाशाही अपने स्वतंत्र आलोचकों से निपटने की शैली, जो इससे संबद्ध नहीं है राजनीतिक दलों या शक्तिशाली धार्मिक संगठनों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारियों का इससे निपटने का यही तरीका रहा है। लोकतंत्र का चोला ओढ़कर असुविधाजनक आवाजें उठाई जा रही हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, इस दौरान 8000 से अधिक लोग लापता हुए हैं पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और बलूचिस्तान और जनजातीय क्षेत्र की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया खैबर-पख्तूनख्वा (जिसे पहले NWFP कहा जाता था) के इलाकों में ये आलोचक पूरे पाकिस्तान में समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त है। फिर भी इन उदारवादियों के साथ किए गए व्यवहार के खिलाफ पर्याप्त विरोध विचारकों और कार्यकर्ताओं की कमी क्यों है? आम शिकायत यह है कि इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे इस पर चिंता व्यक्त करते हैं।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दिवंगत गवर्नर सलमान का मामला तासीर की उनके ही सुरक्षा गार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौत की सजा, और जब उसे फांसी दी गई तो बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर आयोजित प्रार्थना में भाग लिया।

सरकार या उसकी एजेंसियों की मनमानी केवल तभी प्रमाणित होती है जब इनमें से कोई भी वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को परेशान किया जाता है या उन पर हमले किए जाते हैं। इस्लामाबाद की क्रूर नीतियों का विरोध करने वाले लोगों की संख्या उनकी नहीं है जब तक वामपंथी वर्ग के हित सुरक्षित रहेंगे, तब तक यह चिंता का विषय रहेगा।

इससे दक्षिणपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच एक बड़ी खाई साफ तौर पर दिखती है पाकिस्तान में वामपंथी खेमे तब भी सक्रिय हैं जब मुद्दे चिंता का विषय हैं दोनों के लिए। चूँकि दक्षिणपंथियों की संख्या, दक्षिणपंथियों की संख्या से कहीं ज़्यादा है वामपंथियों को तो और भी ज्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। उनकी दयनीय दशा है। इस संबंध में दिया जाने वाला एक प्रसिद्ध उदाहरण है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दिवंगत गवर्नर सलमान का मामला तासीर की उनके ही सुरक्षा गार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौत की सजा, और जब उसे फांसी दी गई तो बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर आयोजित प्रार्थना में भाग लिया। ऐसी प्रार्थनाएँ (नमाज़-ए-जनाज़ा) 88 थीं | 21वीं सदी में सत्ता की राजनीति पाकिस्तान के कई शहरों में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों की संख्या तासीर की नमाज़-ए-जनाज़ा में जो कुछ लिखा गया था, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती यह कोई सुखद परिदृश्य नहीं है; इसके लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता है।

माना जाता है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के पक्षधरों द्वारा दिया गया है। हर किसी को अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति होनी चाहिए, असुविधा की परवाह किए बिना, किसी भी प्रकार के डर के बिना यदि पाकिस्तान आधुनिक और उदारवादी देश के रूप में गिना जाना चाहता है तो उसे धमकी देनी होगी।

****

समकाल: जन आक्रोश को दर्शाती कविताएं

-अंकुर कुमार

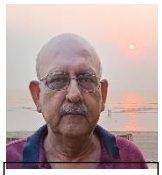
सधांश मिश्र

यह संग्रह ख़ास तौर पर उस युवा पीढ़ी के लिए है जिसे कठमुल्लापन, धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य और उससे सम्बन्धित इतिहास, गंगा-जमुनी संस्कृति जैसे शब्दों / अवधारणाओं को पढ़ने या समझने की फुर्सत ही नहीं मिली। यह भी हो सकता है कि इतिहास की सही और तथ्यात्मक जानकारी अनेकानेक कारणों से हमारे इन युवा दोस्तों तक नहीं पहुँच पाई। यहाँ, मैं यह बात जोड़ना ज़रूरी समझता हूँ कि अधूरा ज्ञान अज्ञान से अधिक ख़तरनाक होता है। आज हम सब दुर्भाग्यवश इसी अधूरे ज्ञान की तरफ बहुतायत में अग्रसर हैं। मैं अपने इन्हीं दोस्तों से अपनी मनःस्थिति साझा करना चाहता हूँ और इन टूटी-फूटी कविताओं के माध्यम से अपने समकाल को दर्ज करने का प्रयास भर कर रहा हूँ।

वरिष्ठ पत्रकार श्री सुधांशु मिश्र की कविताओं का संग्रह 'समकाल' कवि के हृदय की पीड़ा और आक्रोश की पुकार है, जो कई भारतीयों के दिल और दिमाग़ की वर्तमान पीड़ा और हताशा को भी प्रतिबिम्बित करता है। नये भारत में प्रधानमंत्री के 'मन की बात' तो अक्सर सुनने को मिलती रहती है, लेकिन दुर्भाग्य से वे आम भारतवासियों के दिल की बात सुनने से इन्कार कर देते हैं। कवि ने अपनी कविताओं में उस क्षोभ, हताशा और आक्रोश को साहसपूर्वक चित्रित किया है।

मोहनदास करमचंद गाँधी, बापू ने कहा था कि जब लगे कि सरकार के

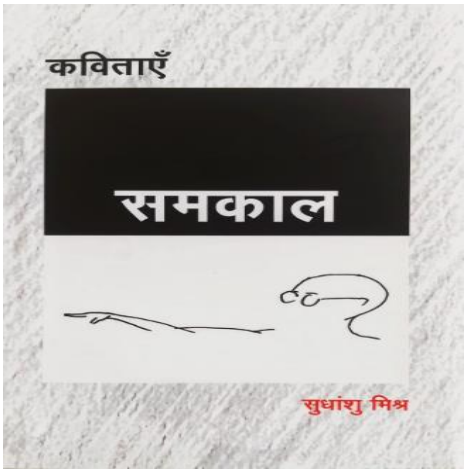

कार्य नागरिकों या राष्ट्रीय हितों के ख़िलाफ़ या हानिकारक हैं, तो नागरिकों को अपनी असहमति की आवाज़ पुरज़ोर तरीक़े से उठानी चाहिये और जब आवश्यक हो तो सरकार के ख़िलाफ़ आन्दोलन भी करें। यदि यह देशद्रोही कृत्य माना जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में राजद्रोह नागरिकों का सद्गुण और अधिकार बन जाता है।

"ग्यारह वर्गों में विभाजित इस समकाल के शीर्षकों को ध्यान से देखने मात्र से यह आसानी से समझा जा सकता है कि कवि सुधांशु की सामाजिक अवस्थिति क्या है, उनकी चिंताएँ क्या हैं, और उनके सरोकार क्या हैं! आज के दौर में, सजग और प्रतिबद्ध माने जाने वाले साहित्यिक लोगों के बीच भी जब वैचारिक विचलन और फिसलन के उदाहरण शर्मनाक हद तक हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अपने विश्वासों पर अविचल रहकर कविकर्म को चुनना, और निश्चयात्मकता के साथ काल-चेतना से समृद्ध कविताएं लिखना एक तरह से कवि का समाज का क़र्ज़ चुकाने जैसा प्रयास है।

"इन छोटी और बड़े आकार की कविताओं की सबसे बड़ी ताक़त इनमें समकाल की सीधी आवाज़ का होना है। सम्प्रेषणधर्मिता इनका ख़ास गुण है और सत्याग्रह इनकी शक्ति है। ये वैसी ही विविधरूपा हैं जैसी विविधरूपा भारतीय संस्कृति है। इनमें कवि रोज़मर्रा की बातचीत की तरह अपने पाठक से संवाद करता है। संवादपरकता भी इनकी ख़ासियत है। आशा है आज का युवा और ऐसा पाठक जो पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं है इनको अवश्य पसंद करेगा।"

"समकाल जैसी किताबे लिखी जानी चाहिए और सभी भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाना चाहिए। वे मन और राजनीतिक आचरण को निर्मल करने और हाल के दिनों में घोले गए जहर को बेअसर करने का एक शक्तिशाली साधन हैं।"

****

द्वितीय वार्षिक डॉ. रमा सहारिया मेमोरियल पुरस्कार समारोह

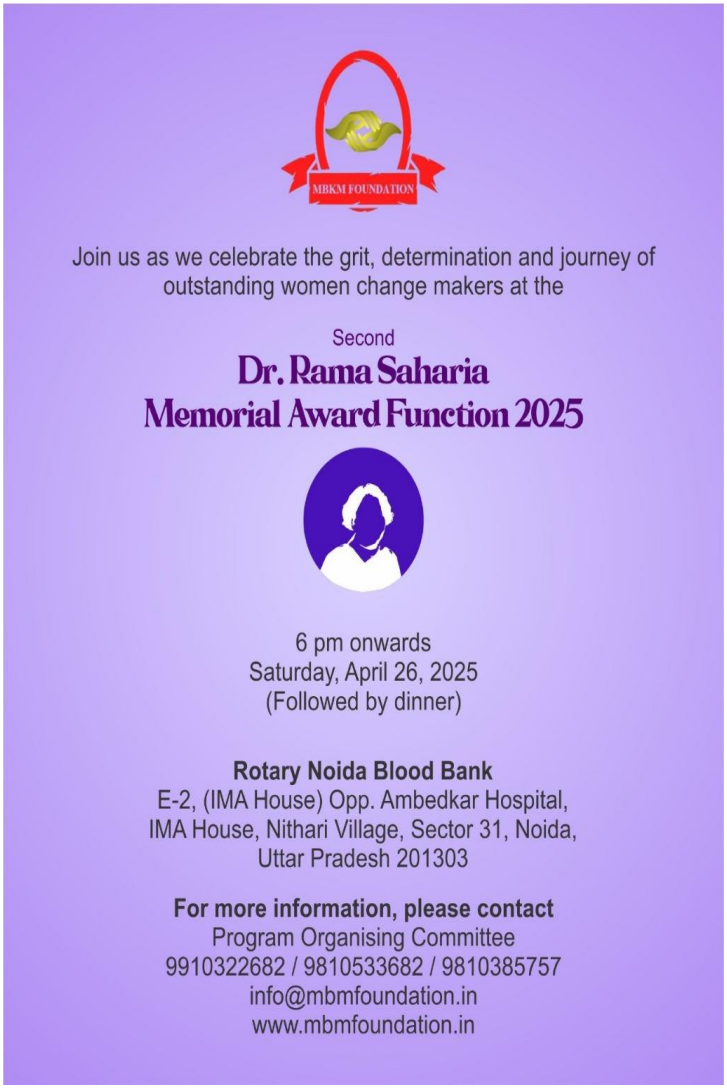

एमबीकेएम फाउंडेशन आपको द्वितीय डॉ. रमा सहारिया मेमोरियल पुरस्कार समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। यह आयोजन 26 अप्रैल, 2025 को आईएमए कॉन्फ्रेंस हॉल, निठारी रोड, सेक्टर 31, नोएडा (दिल्ली-एनसीआर) में आयोजित हो रहा है ।

प्रोफेसर (डॉ.) अर्चना वर्मा की अध्यक्षता में सात सदस्यीय चयन समिति, योग्य व्यक्तियों के नामांकन प्राप्त किया, जिनमें होनहार युवा मीडिया पेशेवर, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य क्षेत्र की प्रेरक महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

डॉ. योगेंद्र नारायण, पूर्व रक्षा सचिव समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री सुनील शास्त्री जी, जाने-माने राजनीतिक नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र, पिछले साल के उद्घाटन पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि थे।

एमबीकेएम फाउंडेशन : एक संक्षिप्त परिचय

श्री मंशी ब्रजराज कमार

दिल्ली में भारत सर्कार द्वारा पजीकृत यह यह फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी सामाजिक सेवा संगठन है जिसका उदेश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार के क्षेत्रों में काम करना है।

सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ पेशेवरों द्वारा स्थापित यह फाउंडेशन समाज को वापस लौटाना चाहता है जिसने उन्हें पेशेवर पहचान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के माध्यम से इतना कुछ दिया है। फाउंडेशन का मानना है कि अब उसे समाज के वंचित और वंचित वर्गों के लिए कुछ स्थायी करना चाहिए। डॉ. रमा सहारिया मेमोरियल पुरस्कार इसी दिशा में एक कदम है।

नैनीताल जिले में ग्रीष्मकालीन परिसर

फाउंडेशन का यह छोटा सा प्रयास अब आपके सामने है। इसे समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण और समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए एक सशक्त रणनीति के रूप में विकसित करने के लिए आपके आशीर्वाद और समर्थन की आवश्यकता है।

पुरस्कारों की अवधारणा और प्रकृति : एक संक्षिप्त परिचय

जब डॉ. रमा का निधन फरवरी, 2024 में हो गया, तो उनके पूर्व सहकर्मियों, छात्रों और उनके चाहने वाले युवा रिश्तेदारों ने उनकी याद को अमर बनाने के लिए कुछ उल्लेखनीय करने का सुझाव दिया था। छात्रवृत्ति देने, बेसहारा बच्चों के लिए काम करने वाले एनजीओ को वित्तपोषित करने और एनजीओ को सीधे अनुदान देने जैसे कई विकल्पों पर विचार किया गया। हालांकि, यह महसूस किया गया कि इस तरह की गतिविधियों से व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा और समाज को सही दिशा में प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, उन महिलाओं को पुरस्कृत करने का फैसला किया गया, जिन्होंने कठिन परिश्रम और संघर्ष के साथ एक असहयोगी माहौल का सामना किया है।

फाउंडेशन ने कॉलेज शिक्षण, मीडिया लेखन, सामाजिक कार्य और ललित कला या सामाजिक रूप से उपयोगी कौशल के क्षेत्रों से युवा और होनहार महिलाओं की पहचान करने और उन्हें पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि पुरस्कार विजेताओं को सामान्य सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से चुना जाएगा, जिन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन संघर्ष किया है।

फाउंडेशन का मानना है कि उसे उन लड़कियों और युवा महिला पेशेवरों को बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और पुरस्कृत करना चाहिए, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया है या कर रही हैं, तथा परिवार और छात्र जीवन की प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से संघर्ष किया है।

फाउंडेशन की पांच सदस्यीय चयन समिति का मानना है कि इस चयन का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन करना नहीं था। बल्कि उन लोगों का चयन करना था जो सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध हों, मानवीय दृष्टिकोण रखते हों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय की अवधारणा के आधार पर समाज के समावेशी विकास के लिए एक दृष्टिकोण रखते हों।

एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी डॉ. रमा सहारिया

डॉ. रमा सहारिया

डॉ. रमा सहारिया उत्तर प्रदेश के एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार से थीं। 1950-1960 के दशक में जब वे छात्रा थीं, तब लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी, लेकिन रूढ़िवादी और परंपरा से बंधी पृष्ठभूमि ने उन्हें उचित नौकरी और एक सुव्यवस्थित पेशेवर करियर अपनाने की अनुमति नहीं दी। वे परिवार की पहली लड़की थीं, जिसने पूर्णकालिक नौकरी की।

वह प्रथम श्रेणी की छात्रा थीं, लेकिन परिवार का ध्यान हमेशा विवाह और गृह प्रबंधन को करियर बनाने पर था। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर डॉ. रमा ने स्नातकोत्तर के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखी और दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी बन गईं।

असली संघर्ष उनकी शादी के बाद शुरू हुआ। उनके पति की पोस्टिंग बाहर थी और तबादला संभव नहीं था। वे 14 साल तक अलग-अलग जगहों पर काम करते रहे और अपनी नौकरी की वजह से अलग-अलग रहे। उन्होंने 3 बच्चों के परिवार का पालन-पोषण किया और संयुक्त परिवार की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाईं। यह एक कठिन संघर्ष था लेकिन अपने करियर को बचाने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉ रमा अत्यधिक रूढ़िवादी सामाजिक पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए काम करने के दृढ़ संकल्प का एक आदर्श बन गईं।

आधुनिक नारीवादी या मुखर न होते हुए भी, रमा ने अपने तरीके से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे का समर्थन किया। उन्होंने उन कॉलेजों में गरीब और वंचित कर्मचारियों और छात्रों की मदद की, जहां वे पढ़ाती थीं और प्रिंसिपल थीं और मीडिया में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लिखती थीं।

1. प्रतिभावान शिल्पकार

2. एक बेहतर चित्रकार थीं

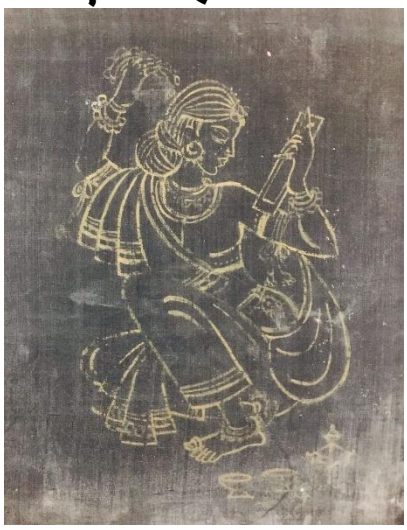

3. मीडिया लेखन में योगदान

Coping with stress

Dec

Dr Rama Saharia

The new age disorders are on the rise due to the new economic structure and breaking away from the cultural heritage. People suffering from typical syndromes go to the physician and later are directed to the psychiatrists. These typical symptoms could be mental stress, mental pressure, being uncomfortable with strangers and many more. In nutshell anything that is not in accordance with the self becomes a symptom.

Surprisingly a majority of the people seem to suffer from mental stress. In the opinion of psychologists anything that puts pressure on mind can be termed as stress. Stress affects adjustment and thereby interferes in day to day performance. Stress is such a phenomenon that it disturbs personal relations also. Someone who is under stress experiences acute disturbance, tension, uneasiness and a constant feeling of restlessness.

Do you understand your child?

Dr Rama Saharia

Does it make a difference if you understand your child? Many parents feel that it is an absurd enquiry so long as they take utmost care of the child and buy whatever he wants.

However expensive the things are not so straight. The parents have to get to know their offspring better.

The best way to understand your child is to spend daily some time with him. Most children feel that there is no one to listen to them when they want to take. Spending time with children will do really good to them.

Caring for the victim

Victimology in India : V.N. Rajan, Allied Publishers Pvt Ltd. Pp. 136, Rs. 40.

The book "Victimology in India" opens a new vista for the rehabilitation of persons who become the helpless victims of crime. We read, write, discuss and investigate a lot about criminals but little is done to understand the psychology and sufferings of their victims.

Victimology is basically a study of crime from the point of view of the victim. It is a science which protects the victim from harassment and *repetition trauma*. The miseries of a victim are countless. He is faced with delays, interrogations postponements, court appearances, and insults at the hands of people and police. Perhaps loss of earnings, waste of time and frustration are his

सत्य साइ बाबा

रमा सहारिया

घटना २३ मई १९४० की है. आंध्रप्रदेश में पुट्टपार्थी के एक छोटे से गांव में एक बालक ने कुछ अजीब बातों से लोगों को चकित कर दिया. बालक का मुख मंडल मधुर मुस्कान व अलौकिक प्रकाश से देदीप्यमान था. उस ने कुछ ही क्षण पूर्व अपने दोस्तों को फल व फूल बांटे थे, जो उस के हवा में हाथ हिलाने मात्र से ही आ गये थे. सब को ऐसा लगा मानो ये वस्तुएं देव लोक से आयी हैं. एक व्यक्ति ने कौतूहलवश पूछा, 'क्या तुम कोई आत्मा या भगवान का रूप हो ?' बालक ने शांत चित्त से उत्तर दिया, 'मैं साईं बाबा हूं. मैंने तुम सब के दुख हरने के लिए जन्म लिया है.' एक व्यक्ति ने पुन: प्रश्न किया, 'उस के लिए हमें क्या करना होगा ?' बालक ने फिर उसी विश्वास से कहा, 'तुम अपने हृदय को पवित्र करो. उस में मेरा निवास होगा. हर बृहस्पतिवार को साईं बाबा की पूजा करो.' सब ग्रामवासी विस्मय में डूब गये. क्या सचमुच ही शिरडी बाबा ने अवतार लिया है ? वे सब भय मिश्रित हर्ष की अवस्था में थे.

महक उठी कुंज गली

परफ्यूम का चुनाव कैसे करें

उचित परफ्यूम का चुनाव बड़ा जरूरी है. अत: खरीदते समय कभी भी जल्दबाजी न करें. इससे आपकी रुचि तथा व्यक्तित्व के सब पहलुओं का पता लग सकता है. मनोवैज्ञानिकों का तो यहां तक कथन है कि सेंट की पसंद के आधार पर ही किसी व्यक्ति की प्रकृति की भी विवेचना की जा सकती है. अत: धैर्यपूर्वक शांतचित्त हो कर सुगंध खरीदें. आप अपनी बहुत सी चीजों को दूसरों की नजर से छुपा सकती हैं, पर परफ्यूम की खुशबू तो बहुत-सी चाही अनचाही बातों को दूसरों के सामने खोलती ही चली जायगी.

वास्तव में उचित परफ्यूम का चुनाव एक समस्या अवश्य है पर समझदारी से काम लेने पर जल्दी ही आप इसमें दक्ष हो जायेंगी. यद्यपि इसका चुनाव व्यक्तिगत पसंद की बात

जी भरकर सोइए

—रमा सहारिया—

जटिलता के कारण ही वह व्यक्ति पर धीरे-धीरे प्रभाव डालती है। धीरे-धीरे व्यक्ति की क्रियाएं घटती जाती हैं, मांस-पेशियां गतिहीन होने लगती हैं। एकाग्रता घटने लगती है और चेतना का क्षेत्र भी सीमित होने लगता है। शारीरिक दृष्टि से पलकें भारी होकर झपकने लगती हैं, अवयव ढीले पड़ने लगते हैं तथा कर्मेन्द्रियां शांत होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त सांस लेने की क्रिया और हृदय का स्पंदन धीमा हो जाता है व शरीर का तापक्रम बढ़ने लगता है।

छात्राओं के बीच एक दिन

— रमा सहारिया —

दिन पर दिन हमें विद्यार्थियों की उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता व अराजकता के विषय में सुनने को मिलता है उनके विद्रोह की चिनगारी किसी न किसी रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो रही है. आखिर इसका क्या कारण है ? क्या समाज ने उन्हें समझने का प्रयत्न किया है ? क्या समाज ने इनकी समस्याओं को उन्हीं के दृष्टिकोण से देखा है ? युवा पीढ़ी को क्रांतिकारी कह कर दोषी ठहरा दिया जाना कहां तक उचित है ? क्या उनका जीवन असंतोष, अतृप्ति, विद्रोह व कुण्ठा में ही व्यतीत हो जायेगा ?

फाउंडेशन की गतिविधियाँ

प्रथम पुरुस्कार समारोह 2024 : एक रिपोर्ट

एमबीकेएम फाउंडेशन द्वारा उनकी स्मृति में स्थापित प्रथम डॉ. रमा सहारिया मेमोरियल पुरस्कार 2024 के अप्रैल माह में नोएडा के एनईए सेमिनार हॉल में भव्य शुभारंभ हुआ।

एक के बाद एक वक्ताओं ने डॉ. रमा, जो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद्, लेखिका और मानवतावादी हैं और जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा महिला सशक्तीकरण के लिए समर्पित किया है, के बारे में भावुक होकर बात की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने न केवल अपने परिवार और दोस्तों के बीच, बल्कि हर जगह एक बड़ा प्रभाव डाला है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना था जिन्होंने अपने पेशे में, खास तौर पर शिक्षक, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया के रूप में, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इतने कम समय में सही उम्मीदवारों को चुनना एक चुनौती थी, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों से बनी जूरी ने आखिरकार छह पुरस्कार विजेताओं पर ध्यान केंद्रित किया।

1. सृष्टि प्रभा लाल (रचनात्मक एवं ललित कला)
2. आलिया अब्बास (मीडिया)
3. शिवानी शर्मा (योग एवं स्वास्थ्य देखभाल)
4. अपर्णा (सामाजिक कार्य)
5. इंदु रानी सिंह (एनजीओ प्रशासन)
6. डॉ. अनु मिश्रा (शिक्षण)

जैसे ही विजेताओं को पुरस्कार सौंपे गए, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को माइक पकड़ने का मौका मिला (आमतौर पर भीड़ भरे पुरस्कार समारोहों में यह मौका उपलब्ध नहीं होता) और वे अपने बारे में और अपने जुनून के बारे में बात कर सके।

कुछ लोग घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन एंकर सीके श्रीवास्तव ने उनका हौसला बढ़ाया और फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दर्शकों को उनकी कहानियाँ बहुत पसंद आईं और उन्होंने उनके प्रयासों और उनके संघर्ष की दिल से सराहना की, जिसके बावजूद उन्होंने अपने प्रयासों में भारी बाधाओं का सामना किया।

हालांकि, सबसे बढ़िया बात अंत में थी। मुख्य अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दो वरिष्ठ अधिकारियों का भाषण, जो सभी को आश्चर्यचकित कर गया, वह था कार्यक्रम के खत्म होने के बाद। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार में रक्षा सचिव जैसे प्रतिष्ठित पदों सहित विभिन्न विभागों को संभालने वाले वरिष्ठ नौकरशाह डॉ. योगेंद्र नारायण ने अपने सेवा के किस्से सुनाकर और यह बताकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया कि कैसे भारत ने अपनी आजादी के 76 वर्षों में जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति की है।

लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री सुनील शास्त्री। हालाँकि उन्होंने कहा कि गुड़गांव से दो घंटे की सड़क यात्रा के बाद वे बहुत थक गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री और अपनी माँ ललिता शास्त्री के बारे में बात करना शुरू किया तो दर्शक पुरानी यादों में खो गए और हर शब्द को ध्यान से सुनते रहे, खास तौर पर युवा जिन्होंने उनके बारे में सिर्फ़ पढ़ा था या उन्हें फ़िल्मों में देखा था।

उन्होंने अपने विनोदी अंदाज में उपस्थित लोगों से कहा कि चूंकि उन्होंने माइक एक राजनेता को सौंप दिया है, इसलिए वह इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे।

एक सरल और ईमानदार राजनेता के रूप में, उन्होंने अपने विनोदी अंदाज में एमबीकेएम फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. प्रदीप माथुर से कहा कि अगले वर्ष अपने कार्यक्रम में उनके लिए एक पुरस्कार आरक्षित किया जाए, जिससे श्रोतागण ठहाके लगाकर हंसने लगे।

पहाड़ी बस्ती में ऊनी वस्त्रों का वितरण

मीडिया मैप समाचार वेबसाइट

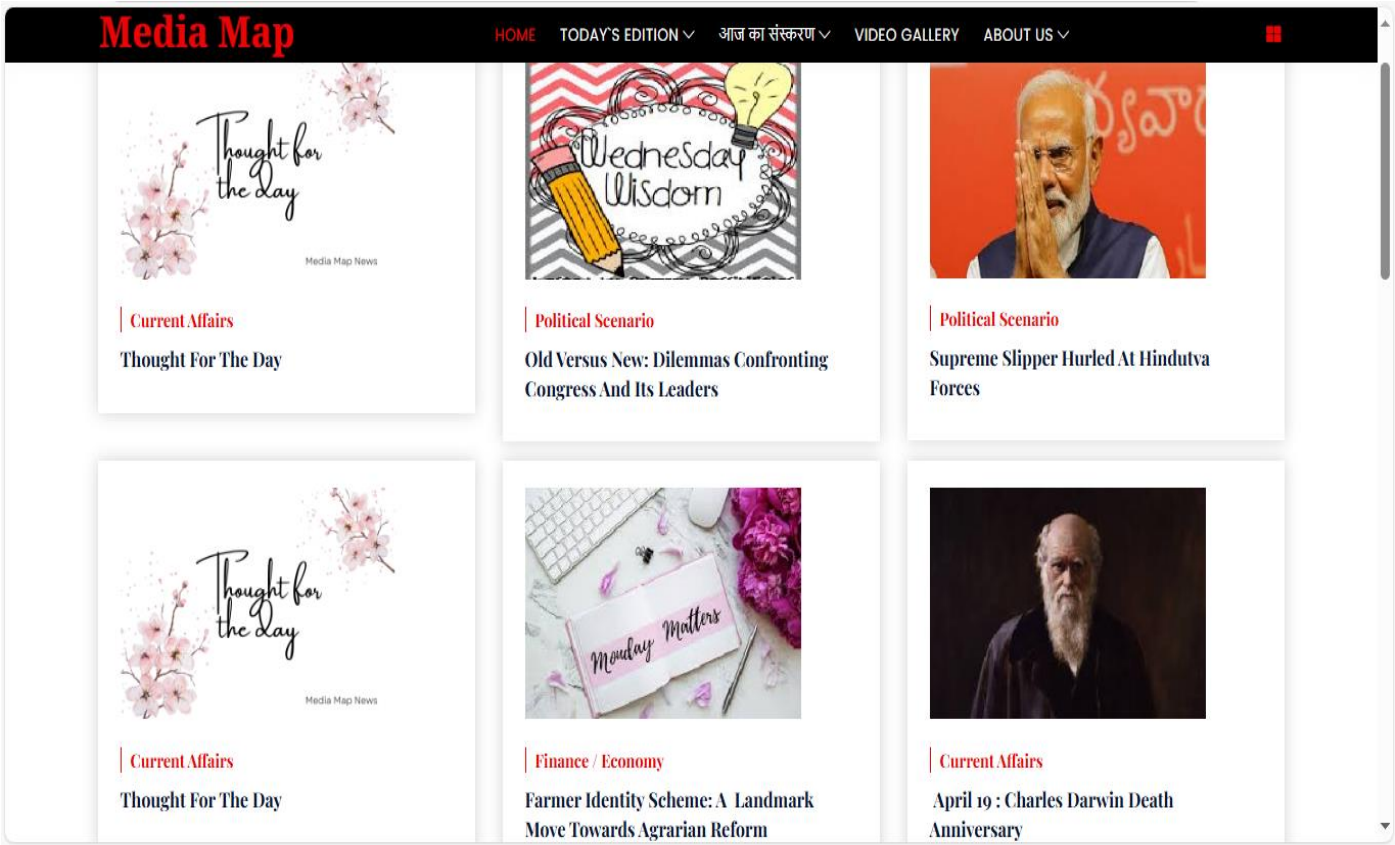

मीडिया मैप यूट्यूब चैनल

मीडिया मैप मासिक पत्रिका प्रकाशन

स्मारक व्याख्यान

कंप्यूटर शिक्षा संस्थान

स्ट्रीट स्कूल में सहयोग

RNI NO. : UPHIN/2016/68336

See Media Map Website

Website link: www.mediamap.co.in

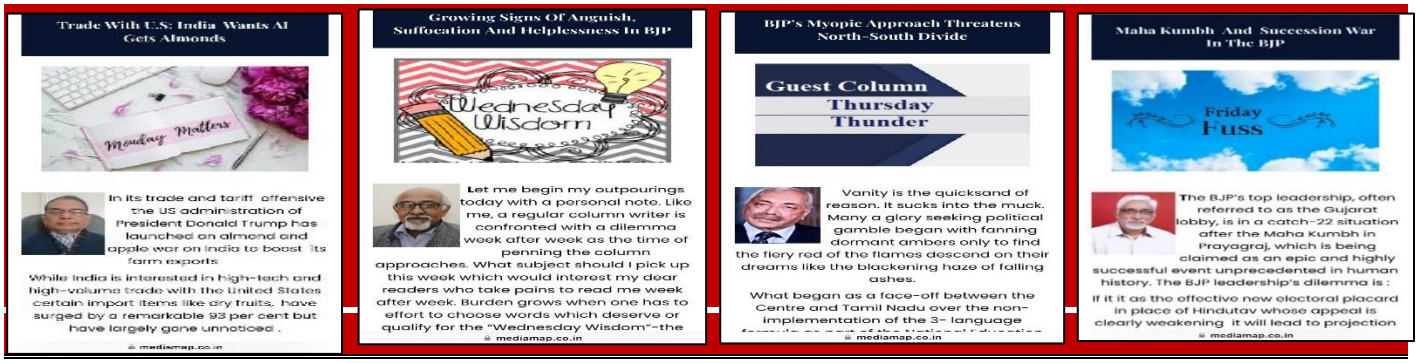

View Media Map YouTube

Media Map News

जनसंवाद 7 : खानपान पर रोक क्यों? Ep- 124
3 views • 4 hours ago

जन संवाद 6 : नेहा हो या कुणाल, व्यंग्य से क्यों डरना? Ep- 123
4 views • 4 hours ago

विविधा 15 : जज को भी छह महीनों की सजा : Ep- 122
27 views • 21 hours ago

विविधा- 14 : कंपनी की तानाशाही - आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर रहें हैं। Ep- 121
6 views • 23 hours ago

आर्थिक सहयोग की अपील

उदार लोकतंत्र और गैर-सांप्रदायिक विश्वास के दर्शन से जुड़ा, मीडियामैप समाचार नेटवर्क एक गैर-व्यावसायिक संगठन है। हम आप जैसे गंभीर और समझदार पाठकों को संबोधित करना चाहते हैं। वरिष्ठ मीडियाकर्मियों के समूह द्वारा किया गया यह एक स्वैच्छिक प्रयास है, जिसका किसी राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक समूह से कोई संबंध नहीं है। मीडिया मैप के प्रकाशन को निरंतर व सुचारु रूप से जारी रखने हेतु आपका सहयोग आवश्यक है।

- ***State Bank of India***
- ***Account No. 43812481024***
- ***IFSC # SBIN0005226***
- ***प्रस्तुत QR कोड को स्कैन करें।***

प्रकाशक
MBKM Foundation, एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन

पंजीकृत कार्यालय
फ्लैट नंबर: 2332, सेक्टर-डी, पॉकेट-2, वसंत कुंज, दक्षिण दिल्ली

Advt.

Scholars Destination

PLEASE CONTACT

9045005700 | 9910322682 | www.sdmotel.com | info@sdmotel.com

BHALUGAAD WATERFALL

KAINCHI DHAM

MUKTESHWAR DHAM

CHAULI KI JALI